▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 299 ▸▸मुंबई, सोमवार , 5 जनवरी 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

अमित शाह का 2026 चुनावी दावा

स्टालिन पर साधा निशाना

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी

एजेंसी । नई दिल्ली

पुदुक्कोट्टई/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। रविवार को पुदुक्कोट्टई में 'तमिलगम थलाई निमिरा तमिलिन पायनम' यात्रा के समापन समारोह में बोलते हुए शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी और जनता इस बार विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सही फैसला करेगी। शाह ने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास रथ में तमिलनाडु को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर कांग्रेस और डीएमके का मुकाबला करेंगे।

भ्रष्टाचार और विफल नीतियाँ

अमित शाह ने डीएमके सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार की चरम सीमा है और जनता को उम्मीदों के अनुसार कुछ भी नहीं मिला। शाह ने कहा, "अगर देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है, तो वह तमिलनाडु में ही है। डीएमके ने अपने घोषणापत्र के वादों में से अधिकांश को पूरा नहीं किया और जनता को निराश किया है।" उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्र पूरी तरह से लाचार हैं। "जनता अब इस विफल और भ्रष्ट सरकार को बदलने का समय जान चुकी है। यही कारण है कि 2026 का चुनाव राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा।"

स्टालिन का पुत्र मुख्यमंत्री नहीं बनेगा

शाह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन के पुत्र उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। उन्होंने कहा कि पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि, लेकिन तमिलनाडु में वंशवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए। शाह ने चुनौती देते हुए कहा, "स्टालिन, आपका यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। जनता इस बार अपनी समझदारी दिखाएगी।" उन्होंने एआईएडीएमके और भाजपा के गठबंधन की मजबूती पर भी जोर दिया और याद दिलाया कि यह गठबंधन 1998, 2019 और 2021 के चुनावों में सफल रहा है।

भाषा और संस्कृति पर जोर: डीएमके पर निशाना

गृह मंत्री ने डीएमके के आरोप को खारिज किया कि एनडीए तमिल भाषा का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के तौर पर, आईएएस और आईपीएस परीक्षाएं तमिल में आयोजित करवाई गईं, और सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की गई। इसके अलावा, तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद भी प्रधानमंत्री की पहल का हिस्सा रहा। शाह ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य को कूड़े के ढेर में बदल दिया गया, हिंदू धर्म और सनातन परंपराओं का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन के समय भी डीएमके के नेताओं ने अघोषित कर्फ्यू लगाया।

भविष्य की योजना और जनता के लिए संदेश

शाह ने कहा कि जनता अब यह तय करेगी कि राज्य में भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति की बजाय विकास, शिक्षा और धर्म के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए और एआईएडीएमके मिलकर तमिलनाडु में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 2026 के चुनाव में सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर मतदान करें। शाह ने कहा कि विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति के मुद्दे अब वोटर्स की पहली प्राथमिकता होने चाहिए।

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री फडणवीस

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और पिछले सात-आठ महीनों में कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है।

चुनावी सभा में विपक्ष पर निशाना

रविवार को बांद्रा में आयोजित भाजपा गठबंधन की चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्ष एक ही मुद्दा उठाने लगता है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी की भी ताकत नहीं है जो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर सके।

मुंबई की सुरक्षा को लेकर आश्वासन

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के निष्ठावान समर्थक और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसलिए मुंबई की सुरक्षा और अस्मिता को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मेट्रो नेटवर्क से आसान होगा सफर

मुंबई की कनेक्टिविटी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में 450 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 150 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक सभी मेट्रो रूट पूरे हो जाएंगे और इसके बाद मुंबई के किसी भी कोने तक केवल 59 मिनट में पहुंचना संभव होगा।

विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में मुंबई सहित पूरे राज्य में विकास कार्य ठप हो गए थे। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास को गति मिली है। कोस्टल रोड परियोजना पूरी हो सकी और बीडीडी चॉल के निवासियों को मुंबई में ही आवास उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मुंबई के मराठी लोग किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले हर पात्र व्यक्ति को उसका हक का घर दिया जाएगा।

बल्लारी हिंसा पर डीके शिवकुमार का हमला

भाजपा कांग्रेस की जीत को पचा नहीं पा रही, पुराने दौर को भूल जाओ

एजेंसी । बल्लारी

बल्लारी, कर्नाटक – कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर भाजपा विधायक जी. जनार्दन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा शिवकुमार ने कहा कि जब तक जनार्दन रेड्डी शहर में नहीं आए थे, तब तक बल्लारी पूरी तरह शांति से भरा हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और जांच एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और कोई राजनीतिक दखल नहीं दिया जाएगा।

महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा स्थापना और विवाद

मुख्यमंत्री के गृह कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिवकुमार ने बताया कि बल्लारी में पहली बार महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। इसके लिए जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी को दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इस शुभ कार्य के लिए बैनर लगाने में क्या गलत था, जबकि भाजपा अपने बैनर उनके घर के सामने भी लगा सकती है।

हत्या की साजिश पर डीके का तंज

जनार्दन रेड्डी द्वारा हत्या की साजिश रचने के दावे को डीके शिवकुमार ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि रेड्डी एक 'ड्रामा मास्टर' हैं और चूंकि वे फिल्म निर्माता भी हैं, इसलिए अभिनय करना उनके स्वभाव में शामिल है। शिवकुमार ने तंज कसते हुए कहा, "जिसके पास सैकड़ों सुरक्षाकर्मी हैं और जिसने किला बना रखा है।

ब्रीफ न्यूज़

शशि थरूर ने वेनेजुएला पर कार्रवाई को बताया नियमों का उल्लंघन

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई एयर स्ट्राइक को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने कहा कि आज की दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का नियम हावी हो गया है और ताकत के आगे नियमों और कानूनों की अनदेखी की जा रही है। शशि थरूर ने स्पष्ट कहा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को हिरासत में नहीं ले सकता, जबकि वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। थरूर ने आगाह किया कि आने वाले समय में ऐसे कदमों के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और विश्व व्यवस्था अस्थिर हो सकती है।

तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश में जिहाद के दो चेहरे उजागर किए

ढाका/नई दिल्ली। निर्वासित और बेबाक लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में जिहाद अब दो अलग-अलग चेहरों के साथ सामने आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही ये दोनों समूह अलग-लग रूप में नजर आते हों, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है – भारत का विरोध करना। नसरीन ने चेतावनी दी कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते कमजोर हुए, तो कट्टरपंथियों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तसलीमा नसरीन ने लिखा कि एक वर्ग वह है जो दाढ़ी-टोपी पहनकर मदरसों से आता है, जबकि दूसरा वर्ग पश्चिमी पोशाक में विश्वविद्यालय की डिग्रियां लेकर निकलता है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी

ब्रुकलिन की कुख्यात जेल में रखे गए और UNSC ने बुलाई इमरजेंसी बैठक

एजेंसी । न्यूयॉर्क/वाशिंगटन

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा है। इस जेल को अमेरिका की सबसे विवादित जेलों में से एक माना जाता है, जहां कई हाई-प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर अमेरिकी कार्रवाई और

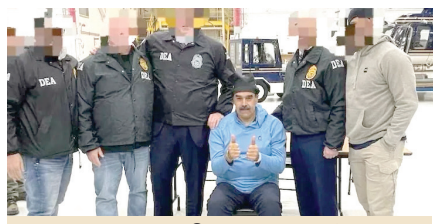

ब्रुकलिन की विवादित जेल में मादुरो का ठहराव

MDC ब्रुकलिन 1990 के दशक में बनी थी और वर्तमान में यहां लगभग 1,300 कैदी बंद हैं। जेल में मैनहट्टन और ब्रुकलिन की फेडरल अदालतों में मुकदमे का इंतजार कर रहे गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और आर्थिक अपराधियों को रखा जाता है। यहां पहले जेफरी एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल, गायक आर. केली, और ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल जाम्बाडा गार्सिया जैसे चर्चित अपराधी रह चुके हैं। मादुरो को शुरू में अलग-थलग रखा जा सकता है, लेकिन बाद में सामान्य हिस्से में रखा गया तो उन्हें उनके पुराने परिचित चेहरे जैसे वेनेजुएला के पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो कार्वाजल और अन्य गिरोह से जुड़े कैदी भी दिखाई दे सकते हैं।

कैदी और जेल की विवादित स्थिति

MDC ब्रुकलिन समुद्र के किनारे इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित है और यहां से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है। हालांकि जेल के हालात लंबे समय से खराब बताए जाते रहे हैं। 2024 में कैदियों के बीच हिंसा और हत्या की घटनाएं भी हुई थीं। जेल प्रशासन ने दावा किया है कि बिजली, पानी, हीटिंग और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की गई है और मादुरो को गिरफ्तार कर USS इयो जिमा वॉरशिप पर ले जाया गया। व्हाइट हाउस ने मादुरो की हथकड़ी में वीडियो जारी की, जिसमें वह अधिकारियों को "हैप्पी न्यू ईयर" कहते दिखाई दिए।

UNSC ने बुलाई इमरजेंसी बैठक

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य एजेंडा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर इस कार्रवाई के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा

अगले 5 दिनों में सर्दी और बढ़ने का अनुमान, IMD ने चेतावनी जारी की

एजेंसी । नई दिल्ली/बीजिंग

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार से कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। सुबह के समय शहर में घनी धुंध ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। रेल और हवाई परिवहन पर भी इसका असर देखा गया। दिल्ली में रविवार को दो तिहाई फ्लाइट्स लेट रहीं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में कुछ समय तक कोहरा बना रह सकता है। मैदानी इलाकों में दिन के कम तापमान और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है। 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आयनगर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

ताइवान पर चीन का दो-टूक संदेश

'एकीकरण अपरिहार्य, अलगाव की कोई गुंजाइश नहीं'

एजेंसी । नई दिल्ली/बीजिंग

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने ताइवान को लेकर चीन के आधिकारिक रुख को दोहराते हुए कहा है कि ताइवान ऐतिहासिक और कानूनी रूप से चीन का हिस्सा रहा है। उनके अनुसार इस मुद्दे पर कोई भ्रम या विवाद नहीं है और चीन की संप्रभुता से जुड़े तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हैं। चीनी राजदूत ने कहा कि अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थापना के साथ ही उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की जगह ली और पूरे चीन का एकमात्र वैध प्रतिनिधि बनी। उन्होंने जोर दिया कि सरकार में बदलाव के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 'चीन' की पहचान और उसकी संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ताइवान सहित पूरे चीन पर पीआरसी का अधिकार बना रहा।

राजनीतिक टकराव, लेकिन संप्रभुता अडिग

शू फेइहोंग ने कहा कि गृहयुद्ध और बाहरी हस्तक्षेप के कारण ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारों के बीच राजनीतिक टकराव बना रहा, लेकिन इससे चीन की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन न तो कभी विभाजित हुआ है और न ही भविष्य में होगा। राजदूत ने यह भी कहा कि ताइवान कभी भी एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा है—न अतीत में, न वर्तमान में और न ही भविष्य में। उनके अनुसार ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और इस वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता।

डीपीपी के कदमों से नहीं बदलेगा भविष्य

ताइवान में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) पर परोक्ष टिप्पणी करते हुए शू फेइहोंग ने कहा कि वहां की सरकार चाहे जो भी बयान दे या नीतिगत कदम उठाए, चीन का पुन: एकीकरण तय है। उन्होंने दोहराया कि इस प्रक्रिया को कोई ताकत रोक नहीं सकती।

भारत-नेपाल सीमा पर सांप्रदायिक तनाव

सोशल मीडिया वीडियो से भड़की हिंसा

एजेंसी । बीरगंज, नेपाल

भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में रविवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बीरगंज और धनुषा जिले में तनाव तब बढ़ा, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री दिखाई देने का आरोप लगाया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस के अनुसार, घटना धनुषा जिले के कमला नगरपालिका के सखुवा मरन क्षेत्र में शुरू हुई। स्थानीय मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है।

सड़क पर प्रदर्शन और आंसू गैस का इस्तेमाल

धनुषा की घटना के विरोध में बीरगंज में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और पुलिस पर पत्थर फेंके। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ हुई। तनाव फैलने पर पुलिस ने आंसू गैस के लगभग आधा दर्जन गोले छोड़े, जिससे स्थिति पर काबू पाया गया।

सांप्रदायिक तनाव और प्रशासन की चेतावनी

पुलिस कार्रवाई के बाद बीरगंज में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई, लेकिन झड़पों में सात पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए। पर्सा के मुख्य जिला अधिकारी भोला दहाल ने सार्वजनिक अपील जारी कर लोगों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों से दूर रहने को कहा।

हिरासत में तीन लोगों से पूछताछ जारी

उन्होंने चेतावनी दी कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह फैलाने और धार्मिक या सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वालों पर प्रशासन कड़ी नजर रखे हुए है। धनुषा पुलिस के प्रवक्ता गणेश बाम ने कहा कि हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है।

मतदान बढ़ाने हेतु दिवा में जागरूकता अभियान

डीबीडी संवाददाता । दिवा

मतदान प्रतिशत बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए कि हर नागरिक लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करे, ठाणे मनपा की दिवा वार्ड कमेटी के तहत वार्ड नंबर 27 और 28 में स्कूली छात्रों के ज़रिए एक असरदार मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। टीएमसी आयुक्त और चुनाव अधिकारी सौरभ राव के मार्गदर्शन में, स्वीप एक्टिविटीज़ की नोडल ऑफिसर डॉ. मिताली संचेती के साथ मिलकर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके में स्वीप एक्टिविटीज़ के ज़रिए वोटिंग के बारे में बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिवा स्टेशन (ईस्ट) के एस. एम. जी. विद्यालय में वोटिंग जागरूकता शपथ और सुबह की प्रभातफेरी का आयोजन किया गया। इस सुबह के जुलूस में, स्टूडेंट्स ने प्लेकार्ड लिए हुए थे और 'वोटिंग एक अधिकार और कर्तव्य है', 'आइए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें' जैसे नारे लगाए और लोगों में जागरूकता पैदा की।

स्कूल के प्रिंसिपल धडवे सर, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने इस एक्टिविटी में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही, स्वीप टीम

छात्रों-छात्राओं के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक

हेड सचिन विलास वैदांडे (टीम नंबर 27 और 28) के नेतृत्व में, मच्छिंद्र साहेबराव मुंडे, गिरीश शेलार (सेंटर कोऑर्डिनेटर–15), शिवा सांगले, निवृत्ति जाधव और स्वीप टीम के सदस्य मौजूद थे। इस जागरूकता एक्टिविटी से लोगों में वोटिंग को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है, और आने वाले चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता से बिना भय के मतदान करने की अपील की गई।

प्रत्यंचा की टंकार से टूटेगा घमंड का भ्रम: प्रताप सरनाईक

हनुमान मंदिर में पूजा के साथ शिवसेना ने किया चुनावी शंखनाद

विनय दूबे । भाईंदर (पू.)

मीरा-भाईंदर नगर निगम चुनाव को लेकर शिवसेना ने जोरदार आगाज किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाईंदर (पूर्व) स्थित बी.पी. रोड के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर शिवसेना के सभी 81 उम्मीदवारों के साथ चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। इस अवसर पर सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिससे पूरा परिसर 'जय श्री राम' के जयघोष से गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए प्रताप सरनाईक ने कहा कि शहर की जनता का विश्वास ही शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विकास की गंगा हर घर तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि मीरा-भाईंदर

का विश्वस्तरीय और सर्वांगीण विकास करना शिवसेना का कर्तव्य है, और इसी उद्देश्य से 81 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतरे हैं।

बालासाहेब और आनंद दिघे के विचारों से प्रेरित लड़ाई

सरनाईक ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे और धर्मवीर स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब के विचारों से प्रेरित होकर शिवसैनिक विकास और विश्वास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसैनिक अपने दम पर मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय पर भगवा फहराने को आतुर हैं और इस बार दमदार प्रदर्शन के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। रविवार को शिवसेना का चुनावी घोषणा-पत्र जारी करते हुए प्रताप सरनाईक ने कहा कि इसमें शामिल लगभग 90 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। ये सभी कार्य पिछले तीन वर्षों में धरातल पर उतारे गए हैं, जो शिवसेना के कुशल, प्रभावी और परिणामोन्मुख कामकाज का प्रमाण हैं।

मेट्रो और सूर्या जलापूर्ति परियोजना अंतिम चरण में

उन्होंने बताया कि मीरा-भाईंदर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना और सूर्या जलापूर्ति परियोजना अपने अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही पूरी होंगी। इन परियोजनाओं से नागरिकों का दैनिक जीवन अधिक सुगम होगा और शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

नरेंद्र मेहता का पलटवार

भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि परिवहन मंत्री भाजपा की नकल कर रहे हैं, यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा-भाईंदर में युति धर्म का पालन नहीं किया गया। मेहता ने कहा कि 16 जनवरी को शहर की जनता घमंड और झूठ का माकूल जवाब देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2017 में नगरसेवक भाजपा के कारण चुने गए थे और इस बार प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से सच्चाई सामने आएगी।

सायन-पनवेल महामार्ग पर सघन स्वच्छता अभियान

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा मुख्य सड़कों के साथ-साथ आंतरिक क्षेत्रों में भी लगातार सघन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को शहर के अत्यधिक व्यस्त सायन–पनवेल महामार्ग पर वाशी से बेलापुर की ओर जाने वाले मार्ग की व्यापक सफाई की गई। अभियान के तहत सड़क और फुटपाथ के

शहर के आंतरिक मार्गों पर भी विशेष सफाई

किनारों पर जमी मिट्टी को ब्रश की सहायता से हटाकर एकत्र किया गया और उसे सुरक्षित रूप से हटाया गया। इसके बाद प्रोसेस्ड पानी से सड़कों की धुलाई की गई। सफाई के लिए जेटिंग स्प्रे का उपयोग किया गया, जिससे धूल के कणों को नियंत्रित करने में मदद मिली।

350 से अधिक कर्मियों की भागीदारी

रविवार की सार्वजनिक छुट्टी के बावजूद यह सघन स्वच्छता अभियान अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार के मार्गदर्शन में, घन कचरा प्रबंधन विभाग के उप आयुक्त डॉ. अजय गडदे के नियंत्रण में तथा मुख्य स्वच्छता अधिकारी रविंद्र इंगळे और स्वच्छता अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित किया गया। इस अभियान में अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छताकर्मी मिलाकर 350 से अधिक लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

आंतरिक इलाकों की प्रमुख सड़कों पर भी अभियान

सायन–पनवेल महामार्ग के साथ-साथ शहर के आंतरिक भागों में स्थित प्रमुख सड़कों जैसे सेक्टर–17 कोपरखैरणे मुख्य मार्ग, रिलायबल टेक पार्क ऐरोली, गजानन चौक से शापुरजी पल्लोंजी साइट सेक्टर–6 सानपाड़ा, जूहूगांव मुख्य मार्ग, शिरवणेगांव आंतरिक मुख्य सड़क और जिजामाता नगर घणसोली में भी सघन सफाई की गई।

वायु गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर

सड़कों पर और किनारों पर जमी मिट्टी हटाकर हवा में धूल की मात्रा कम करने के लिए यह अभियान महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही एनकैप वाहनों के माध्यम से प्रोसेस्ड पानी का फव्वारे जैसी स्प्रे कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

जुपिटर मैराथन में गूंजा मतदान का संदेश

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका और जुपिटर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जुपिटर मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया। इस मैराथन के माध्यम से 15 जनवरी 2026 को होने वाले ठाणे महानगरपालिका के आम चुनावों को लेकर मतदाता जागरूकता का विशेष संदेश दिया गया। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता बैनर और प्लेकार्ड लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की। 'मतदान एक अधिकार और फर्ज है' और 'चलो 15 जनवरी को मतदान करें' जैसे संदेशों के जरिए युवाओं और

धावकों ने किया वोट देने का आह्वान

नागरिकों को वोटिंग के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की विभिन्न श्रेणियों में मैराथन आयोजित की गई। इस मौके पर ठाणे मनपा के स्वीप (SVEEP) इनिशिएटिव के नोडल अधिकारी मनीष जोशी, उपायुक्त मिताली संचेती सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिक का संदेश

ठाणे मनपा के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत मैराथन में साफ-सफाई और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश भी दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर स्वच्छता, निर्भीक मतदान और नागरिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। मैराथन स्थल पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर धावकों ने तस्वीरें लीं, जहां लिखा था- 'मैं ठाणे का एक जागरूक नागरिक हूं, मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करूंगा।' कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने मतदान करने की शपथ भी ली।

मनपा की अपील: ठाणे महानगरपालिका प्रशासन ने सभी योग्य मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। मैराथन के जरिए दिया गया यह संदेश शहर में मतदान को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

नारायण राणे ने राजनीति से संन्यास का संकेत दिया

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में लंबे समय से सगे भाई नितेश राणे और निलेश राणे के बीच चल रहे विवाद की खबरों के बीच अब शांति का संदेश सामने आया है, क्योंकि रविवार को दोनों के पिता और भाजपा नेता नारायण राणे ने साफ कहा कि उनके दोनों बेटों के बीच कोई टकराव नहीं है, और चुनाव समाप्त होने के बाद परिवार में सब सामान्य है, साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत भी दिया।

रविवार को स्थानीय चुनावों के मद्देनजर नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग जिले में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें पालक

बोले- नितेश और निलेश में कोई टकराव नहीं

मंत्री नितेश राणे, विधायक दीपक केसकर और निलेश राणे भी कंकावली में मौजूद थे, इस अवसर पर नारायण राणे ने कंकावली भाषा में भाषण देते हुए कहा कि उन्होंने 'नारा एक्चा' का अर्थ पूछा, क्योंकि हर जगह इस शब्द से लिखे बैनर लगे थे, और जब उन्होंने पूछा, तो उन्हें समझ आया कि नारायण राणे का मतलब 'नारा एक्चा' ही है।

भाजपा मेरे जीवन की आखिरी पार्टी

नारायण राणे ने कहा कि उन्हें यहां आकर समझ आया कि सभा का आयोजन क्यों किया गया, और जब उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा उनके जीवन की आखिरी पार्टी होगी, उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी पद योग्यता और मेहनत के बल पर हासिल किए हैं, और अगर वे जीवित रहे, तो सम्मान के साथ जीवन जीने का उनका लक्ष्य पूरा होगा, उनका कहना था कि वे अपने दम पर काफी हैं और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, हमारे पीछे कौन है यह भी उन्हें पता है।

नितेश और निलेश के बीच कोई विवाद नहीं

नारायण राणे ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति राणे परिवार से दूर होता है, तो उसे बड़े फायदे मिल सकते हैं, लेकिन राणे परिवार हमेशा अपने साथ रहेगा, उन्होंने नितेश और निलेश के बीच राजनीतिक विवाद पर स्पष्ट किया कि राजनीति इसलिए होती है क्योंकि दोनों अलग-अलग पार्टियों में हैं, क्या चुनाव में सभी लोग पैसे नहीं बांटते, फिर प्रचार क्यों, दोनों भाई खुश हैं और अच्छा काम कर रहे हैं

नड्डा का भरोसा, संन्यास पर प्रतिक्रिया

नारायण राणे ने बताया कि लोकसभा में जाने से पहले भी उन्होंने टिकट की इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 'हम तुम्हें राजनीति से नहीं छोड़ेंगे,' नारायण राणे ने स्वीकार किया कि वे थोड़ा घमंडी हैं और कभी खुद को किसी से कम नहीं मानते, लेकिन अब उन्हें कहीं तो रुकना होगा, उन्होंने साफ किया कि राणे बनाम राणे जैसी स्थिति नहीं होगी, हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी।

56 वर्षीय व्यक्ति ने 30 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर फांसी लगाई

राजनीतिक नेता पर गंभीर आरोप

डीबीडी संवाददाता । पुणे

पुणे शहर में महापालिका चुनाव प्रचार की शुरुआत के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 56 वर्षीय सादिक कपूर ने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने शहर में सनसनी मचा दी क्योंकि मृतक ने 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और अपने शरीर पर भी कथित राजनीतिक उम्मीदवार का नाम लिखा था। घटना की सूचना मिलते ही लष्कर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ससून अस्पताल भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के पीछे मनसिक दबाव, जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन की वजहें

सामने आ रही हैं। सादिक कपूर का ऑफिस पुणे के कैंप इलाके की ई-स्ट्रीट स्थित कॉम्प्लेक्स में था। सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने पहले सुसाइड नोट लिखा और फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार, सादिक कपूर ने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक नेता का नाम लिखा था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के उम्मीदवार फारूक इनामदार ने उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा। परिजनों का कहना है कि यह दबाव जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन से जुड़ा था, जिससे सादिक कपूर मानसिक रूप से टूट गए और उन्होंने यह कदम उठाया।

मृतक का आपराधिक इतिहास भी सामने आया

पुलिस ने बताया कि सादिक कपूर के खिलाफ पहले MCOCA (मकोका) के तहत कार्रवाई हो चुकी थी और उनके खिलाफ दो गंभीर मामले दर्ज थे। इसके अलावा, उनके कुख्यात अपराधी टिपू पठाण से संबंध होने की जानकारी भी मिली है। पुलिस का कहना है कि पुराने जमीन विवाद, पैसों के लेन-देन और मानसिक दबाव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच जारी है। पुलिस फिलहाल सुसाइड नोट की सामग्री, राजनीतिक आरोप, जमीन विवाद और आर्थिक लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

फारूक इनामदार सैयद नगर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वे नगरसेवक भी रह चुके हैं।

दिवा में शपथ और प्रभातफेरी से मतदाता जागरूकता अभियान, मतदान बढ़ाने पर जोर

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और हर नागरिक को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ठाणे महानगरपालिका की दिवा प्रभाग समिति के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 और 28 में प्रभावी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

ठाणे मनपा आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ राव के मार्गदर्शन तथा स्वीप गतिविधियों की नोडल अधिकारी डॉ. मिताली संचेती के सहयोग से, स्वीप (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत शहरभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिवा स्टेशन (पूर्व) स्थित एस. एम. जी. विद्यालय में मतदाता जागरूकता शपथ और प्रभातफेरी

का आयोजन किया गया। प्रभातफेरी के दौरान छात्रों ने 'वोट देना अधिकार और कर्तव्य है' तथा 'लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें' जैसे नारों के जरिए नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया।

शिक्षक, अभिभावक और छात्र रहे शामिल

इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य धडवे सर, शिक्षकगण, छात्र और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बच्चों की सहभागिता ने अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाया। वार्ड 27 और 28 के लिए गठित स्वीप टीम के प्रमुख सचिन विलास वैदांडे के नेतृत्व में मच्छिंद्र साहेबराव मुंडे, गिरीश शेलार (सेंटर कोऑर्डिनेटर–15), शिवा सांगले, निवृत्ति जाधव सहित अन्य टीम सदस्य मौजूद रहे। इस जनजागरूकता गतिविधि के माध्यम से नागरिकों में मतदान को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। मनपा प्रशासन ने सभी मतदाताओं से बिना किसी डर के अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है।

सड़क दुर्घटना मामला

एमएसआरटीसी को मृतक के परिजनों को 36.31 लाख रुपए मुआवज़ा चुकाने का निर्देश

डीबीडी संवाददाता । कल्याण

ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने राज्य परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 36.31 लाख रुपए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना एमएसआरटीसी की बस और एक मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की टक्कर में हुई थी। न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने 1 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के लिए बस चालक की लापरवाही प्रमुख

कारण रही, हालांकि मोटरसाइकिल सवार की भी आंशिक जिम्मेदारी तय की गई है। मृतक सुभाष महादु शिंदे (44) कल्याण-मुरबाड रोड पर मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही राज्य परिवहन की बस से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। शिंदे की पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता ने न्यायाधिकरण में मुआवज़े की याचिका दायर की थी। परिवार की ओर से बताया गया कि सुभाष शिंदे एक माल ढुलाई सेवा कंपनी में स्थायी कर्मचारी थे और उनकी मासिक आय 26,000 रुपए से अधिक थी।

80 प्रतिशत जिम्मेदारी बस चालक की

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि यह आमने-सामने की टक्कर थी, इसलिए दोनों चालकों की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही 20 प्रतिशत और बस चालक की लापरवाही 80 प्रतिशत निर्धारित की गई। इन तथ्यों के आधार पर न्यायाधिकरण ने मृतक के परिजनों को कुल 36,31,633 रुपए मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। साथ ही एमएसआरटीसी को मार्च 2021 में याचिका दायर किए जाने की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

ठाकरे भाइयों की साथ दिखी सियासी ताकत

मराठी अस्मिता और वादों की बौछार से गरमाया BMC चुनाव

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी (शरद पवार गुट) के संयुक्त चुनावी घोषणा-पत्र के जारी होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता, मराठी मानुष का मुद्दा, लोकलुभावन घोषणाएं और चुनाव आयोग में पहुंचा कानूनी विवाद—इन सभी ने बीएमसी चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है।

शिवसेना भवन में दिखी ठाकरे भाइयों की नजदीकी

रविवार को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वर्षों बाद एक मंच पर शिवसेना भवन में साथ नजर आए। राज ठाकरे की शिवसेना भवन में मौजूदगी को प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मौके पर राज ठाकरे ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि शिवसेना भवन से उनका भावनात्मक जुड़ाव आज भी बना हुआ है। वहीं शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस मुलाकात को 'परिवार के पुनर्मिलन' जैसा बताया।

उद्धव ठाकरे का महायुति पर हमला

कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले चुनावों में वोटों की हेराफेरी हुई और अब विपक्षी दलों के नेताओं और उम्मीदवारों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

मराठी मानुष और मेयर पद का मुद्दा

राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में मेयर मराठी और हिंदू ही होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन का घोषणा-पत्र मराठी भूमिपुत्रों के अधिकारों और सम्मान पर केंद्रित है। वहीं उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या मराठी पहचान को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। यह मुद्दा अब बीएमसी चुनाव का केंद्रीय एजेंडा बनता दिख रहा है।

चुनाव आयोग में पहुंचा मामला

इस बीच अधिवक्ता डॉ. गुणरत्न सदावर्ते ने संयुक्त घोषणा-पत्र को लेकर महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कई घोषणाएं असंवैधानिक और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हैं तथा इन्हें चुनावी प्रलोभन की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इससे बीएमसी चुनाव से पहले कानूनी पेंच भी गहराता नजर आ रहा है।

सियासी मुकाबला और तेज

बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे भाइयों की एकजुटता, मराठी अस्मिता का उभार, बड़े वादे और कानूनी विवाद—इन सभी ने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। अब निगाहें चुनाव आयोग के रुख और मतदाताओं के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी।

भाजपा का पलटवार

बीजेपी ने इस संयुक्त घोषणा-पत्र को 'झूठे वादों का दस्तावेज' बताया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने आरोप लगाया कि यह केवल चुनावी आकर्षण है और पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे वादों से भ्रमित होने वाली नहीं है।

संयुक्त घोषणा-पत्र में बड़े वादे

शिवसेना-मनसे-एनसीपी (शरद पवार गुट) के संयुक्त घोषणा-पत्र में नागरिक सुविधाओं और सामाजिक योजनाओं पर जोर दिया गया है। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, सस्ती भोजन योजना, रोजगार और स्वरोजगार सहायता, प्रॉपर्टी टैक्स में राहत, BEST बस सेवा में सुधार, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं।

एफडीए की सख्त कार्रवाई

प्रतिबंधित हुक्का कारोबार पर बड़ा प्रहार

31.67 करोड़ रुपये का स्टॉक जब्त, फैक्ट्री सील

पुणे। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित तंबाकू और हुक्का उत्पादों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष सहायक मंत्री नरहरी झिरवल के निर्देशों के बाद राज्यभर में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुणे जिले के मावल तालुका में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये का प्रतिबंधित हुक्का स्टॉक जब्त किया गया है।

एफडीए की टीम ने 2 जनवरी 2026 को मावल तालुका के टाकवे गांव स्थित 'मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि.' कंपनी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित हुक्का और उससे जुड़ी सामग्री बरामद की गई। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी अस्मिता टोणपे की शिकायत के आधार पर की गई।

जांच रिपोर्ट में निकोटिन की पुष्टि

जानकारी के मुताबिक, 1 दिसंबर 2025 को कंपनी के उत्पादों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। मुंबई स्थित खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूनों में निकोटिन पाए जाने की पुष्टि हुई, जिसे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक माना जाता है। यह कार्रवाई 16 जुलाई 2025 को राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर की गई।

छापेमारी के दौरान विभिन्न फ्लेवर वाले तैयार हुक्का उत्पाद, कच्चा माल और फ्लेवर जब्त किए गए। इसके बाद कंपनी परिसर को सील कर दिया गया। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन और भंडारण किया जा रहा था। इस प्रकरण में कंपनी संचालक आसिफ फजलानी, फैजल फजलानी और सहायक प्रबंधक अनिल कुमार चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 3(5), 123, 223, 274, 275 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 30, 26, 27 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूर्व महापौर और शिवसेना यूबीटी की नेता शुभा राउल ने दिया इस्तीफा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र के मुंबई की पूर्व महापौर और शिवसेना यूबीटी की नेता शुभा राउल ने रविवार को अपना इस्तीफा शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव को भेज दिया है। इसके बाद शुभा राउल ने मंत्री आशीष शेलार और भाजपा नेता प्रवीण दरेकर से मुलाकात की है। इससे संभावना है कि शुभा राउल बहुत जल्द भाजपा में शामिल होंगी। ऐन मुंबई नगर चुनाव के समय शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है।

शुभा राउल ने रविवार को शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को भेजे पत्र में कहा है कि पार्टी में उन्हें बहुत सम्मान मिला। लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं के विकास काम के लिए अब अलग रास्ता चुन रही हैं। इसके बाद आज शुभा राउल भाजपा नेता आशीष शेलार

और प्रवीण दरेकर से मिलीं। हालांकि अभी तक शुभा राउल को भाजपा में शामिल किए जाने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है।

उल्लेखनीय है कि शुभा राउल मुंबई नगर के दहिसर इलाके के वार्ड क्रमांक ८ में रहती हैं और यहां लगभग चार सीटों पर राउल वर्चस्व है। इसलिए इस क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी और मनसे को नुकसान होने की जोरदार चर्चा हो रही है।

बीमारी और मानसिक तनाव ने ली दो जिंदगियां

पुणे में मां-बेटी की मौत से सनसनी

पुणे। शहर के वारजे मालवाड़ी इलाके से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी गंभीर रूप से बीमार दो वर्षीय बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा फैल गया है।

मृतकों की पहचान दो साल की शार्वी आदिनाथ देवडकर और उसकी 28 वर्षीय मां छाया देवडकर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, परिवार गोकुलनगर इलाके में रहता था। शार्वी लंबे समय से हड्डियों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। बेटी की लगातार बिगड़ती तबीयत और लंबे इलाज को लेकर मां छाया मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी। घटना के दिन शार्वी के पिता आदिनाथ देवडकर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। दोपहर में जब वे घर लौटे, तो घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। बेटी झूले में बेसुध अवस्था में पड़ी थी, जबकि पत्नी छाया घर के भीतर फंदे से लटकी मिली।

पुलिस जांच में हत्या की पुष्टि

घबराए आदिनाथ ने तुरंत वा रजे मालवाड़ी पुलिस थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त शीतल जानवे और पुलिस निरीक्षक ढेंडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मां और बेटी दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मासूम शार्वी की मौत गला घोंटने से हुई थी, जबकि मां की मौत आत्महत्या से हुई। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि बेटी की गंभीर बीमारी और उससे जुड़ा मानसिक दबाव इस घटना की मुख्य वजह हो सकता है।

हर पहलू से जांच जारी

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में वारजे मालवाड़ी पुलिस ने बच्ची की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ कर घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

निर्विरोध जीत पर सियासी घमासान

फडणवीस बोले-अदालत नहीं, जनता तय करेगी फैसला

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले निर्विरोध निर्वाचित पार्षदों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा इन चुनावों को अदालत में चुनौती देने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण जनता का जनादेश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

राज्य की 29 नगरपालिकाओं में 2,869 सीटों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। इन चुनावों में कुल 33,606 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मतदान से पहले ही 68 सीटों पर पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है।

कोर्ट जाने की धमकी पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

रविवार को चंद्रपुर में एक रोड शो के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विपक्ष चाहे तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के मत से ही तय होगा। उन्होंने कहा, "जनता की अदालत सबसे बड़ी है। अगर जनता ने किसी को चुना है, तो वही जनादेश सर्वोपरि रहेगा।"

चंद्रपुर में रोड शो और जनसभा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने चंद्रपुर में भाजपा और महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, मंत्री अशोक उइके और विधायक किशोर जोरगेवार मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा और शिवसेना ने ही चंद्रपुर में वास्तविक विकास कार्य किए हैं।

विपक्ष पर हार का डर

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कई निर्दलीय और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को अपनी संभावित हार साफ दिखाई दे रही है और इसी वजह से वह विवाद खड़ा कर रहा है।

विकास के नाम पर समर्थन की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहरी विकास के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार को समर्थन दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि महायुति को जनता का समर्थन मिलता है।

उबाठा-मनसे का वचननामा पुराने दस्तावेज़ की कॉपी-पेस्ट : राहुल शेवाले

हिंदू और हिंदुत्व शब्द पूरी तरह गायब

राहुल शेवाले का उबाठा-मनसे पर हमला

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महानगरपालिका चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वचननामा पर राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के महासचिव और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने इस वचननामा को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उबाठा और मनसे का यह वचननामा वर्ष 2017 के पुराने वचननामा की हूबहू नकल है, जिसमें न तो कोई नया विचार है और न ही मुंबई के वास्तविक मुद्दों का समाधान। राहुल शेवाले ने कहा कि पूरे वचननामा से 'हिंदू' और 'हिंदुत्व' जैसे शब्द जानबूझकर हटा दिए गए हैं। यहां तक कि बालासाहेब ठाकरे के नाम के आगे से 'हिंदुहृदयसम्राट' शब्द भी गायब कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक विशेष समुदाय को खुश करने और वोट बैंक साधने के लिए किया गया है, जो बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात है।

2017 का वचननामा फिर से पेश किया गया

शेवाले ने दावा किया कि जिस वचननामा को नई सोच और नए वादों के रूप में पेश किया जा रहा है, वह असल में 2017 के चुनावी वचननामा की कॉपी-पेस्ट है। उन्होंने कहा कि न तो मुंबई की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है और न ही नागरिक समस्याओं पर ठोस रोडमैप दिया गया है।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मराठी अस्मिता की बात करने वाली पार्टियों के वचननामा में मराठी से ज़्यादा अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे की चुप्पी को लेकर भी उन्होंने भूमिका स्पष्ट करने की मांग की।

राहुल शेवाले ने कहा कि वचननामा में भले ही बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई हो, लेकिन उसमें उनके विचारों की झलक नहीं है। उन्होंने इसे शिवसैनिकों और मराठी मानुष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला दस्तावेज़ बताया। शेवाले ने सवाल किया कि ढाई साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुंबई में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और कोळीवाड़ों के अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने जैसे अहम फैसले क्यों नहीं लिए गए।

शिवसेना यूबीटी-मनसे का संयुक्त वचननामा जारी

मुंबई के विकास और मराठी अस्मिता पर फोकस

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई के दादर स्थित सेना भवन में संयुक्त रूप से नगर निगम चुनावों के लिए अपना वचननामा जारी किया। घोषणा पत्र में मुंबई समेत राज्य की सभी नगर निगमों के विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया गया है।

वचननामा जारी करते हुए दोनों ठाकरे भाइयों ने स्पष्ट किया कि मुंबई सहित राज्य की सभी नगर निगमों में महापौर हिंदू और मराठी होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज मराठी महापौर की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने अतीत में गैर-मराठी महापौर और उपमहापौर बनाए हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग नगर निगम चुनावों में मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।

महिलाओं और नागरिक सुविधाओं पर विशेष जोर

शिवसेना यूबीटी और मनसे के संयुक्त घोषणा पत्र में कई लोककल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। इनमें घरेलू कामगार महिलाओं का पंजीकरण, पंजीकृत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की 'स्वाभिमान निधि', कामकाजी महिलाओं और अभिभावकों के लिए डे-केयर सेंटर, पेट क्लीनिक और बालासाहेब ठाकरे सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट फंडिंग स्कीम शामिल हैं। घोषणा पत्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खाली पद भरने, हर वार्ड में 'आजी-आजोबा पार्क' विकसित करने, 700 वर्ग फीट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने और कचरा टैक्स समाप्त करने का वादा किया गया है।

इसके साथ ही म्युनिसिपल स्कूलों को बिल्डरों के हाथों में जाने से रोकने, 10वीं के बाद 12वीं तक जूनियर कॉलेज शुरू करने, मुंबई पब्लिक स्कूलों को अपग्रेड करने और मराठी स्कूलों में डिजिटल पहल लागू करने की बात कही गई है।

भ्रष्टाचार के आरोप, जांच का ऐलान

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई नगर निगम सहित अन्य नगर निगमों में 300 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना काल पर लिखी गई एक किताब पर राज्य चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी उस किताब को जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो उन्हें रोका जाए।मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि कोई भी सत्ता की स्थायी बेल्ट पहनकर नहीं आता। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। उन्होंने कहा कि गलत राजनीतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना खतरनाक हो सकता है।

राज ठाकरे ने दावा किया कि वे पिछले 10 वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में यूपी-बिहार जैसी राजनीति हावी हो रही है। उन्होंने दोहराया कि मराठी मानुष के अधिकारों की लड़ाई मनसे हमेशा लड़ती रहेगी।

आरपीएफ की वर्दी बनाकर साइबर ठग सक्रिय

नागपुर। पुलिस के नाम पर ठगी के बाद अब साइबर अपराधियों ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी अपना नया हथियार बना लिया है। ठग खुद को आरपीएफ अधिकारी बताकर आम नागरिकों को फोन और वीडियो कॉल के ज़रिए डराते हैं और उनके किसी करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किए जाने का झूठा दावा कर ऑनलाइन रकम ऐंठ लेते हैं। इस नए साइबर फ्रॉड को 'डिजिटल अरेस्ट' का नाम दिया जा रहा है। इस ठगी में आरोपी पीड़ित को फोन कर उसके बेटे, भाई या किसी नजदीकी रिश्तेदार का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वह बिना टिकट यात्रा करते हुए, गैस सिलेंडर के साथ या किसी संदिग्ध गतिविधि में आरपीएफ की गिरफ्त में है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को घबराया जाता है।

फर्जी वीडियो कॉल और नकली पहचान पत्र

साइबर ठग वीडियो कॉल पर खुद को आरपीएफ अधिकारी बताकर नकली पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज और वर्दी जैसी पृष्ठभूमि दिखाते हैं। कई मामलों में वे किसी व्यक्ति की नकली आवाज भी चलाते हैं, जिससे पीड़ित को लगता है कि उसका रिश्तेदार वास्तव में मुसीबत में है।डर के माहौल में पीड़ित को व्हाट्सऐप पर क्यूआर कोड भेजा जाता है और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है। इनकार करने पर एफआईआर, गिरफ्तारी और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। ठग यह भी कहते हैं कि मामला गोपनीय है और किसी से चर्चा नहीं की जाए।साइबर विशेषज्ञों का साफ कहना है कि आरपीएफ या कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए जुर्माना नहीं वसूलती। 'डिजिटल अरेस्ट' नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया देश में मौजूद ही नहीं है। यह पूरी तरह से साइबर ठगी का तरीका है।

पश्चिम रेलवे

सड़क ऊपरी पुल (ROB) का निर्माण कार्य

उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे, सूरत-395006, ई-निविदा सूचना संख्याः Dy.CE(C) ST/174(R),दिनांकः 30.12.2025 आमंत्रित करते हैं। कार्य का नामः मुंबई मंडल के अंतर्गत उधना-उकाई सोंगध खंड में कि.मी. 15/12-13 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 16 के स्थान पर दो लेन सड़क ऊपरी पुल (ROB) का अप्रोच सहित (एंड टू एंड) निर्माण कार्य। अनुमानित निविदा मूल्य : 51,73,38,684.19 बयाना धनराशि (EMD): 27,36,700/- ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 21.01.2026 को 15:00 बजे तक ई-बोली खोलने की तिथि एवं समयः 21.01.2026 को 15:30 बजे अधिक जानकारी एवं विस्तृत निविदा दस्तावेज हेतु कृपया IREPS वेबसाइट देखें: www.ireps.gov.in 0973

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

संपादकीय

विकसित भारत की चुनौती

नव वर्ष के आगमन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश अब 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार हो चुका है। इसके तुरंत बाद उन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच 'प्रगति' की बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार, प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक परिवर्तन अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 में किए गए जिन प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया, उनमें जीएसटी में व्यापक बदलाव, बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, मनरेगा में आमूलचूल परिवर्तन, श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सुधार शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीएसटी सुधारों से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है, किंतु अन्य सुधारों के परिणाम सामने आने में समय लगेगा। मोदी सरकार ने बीते वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के साथ-साथ नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना और देश को तेज विकास की राह पर ले जाना है। यह भी सत्य है कि प्रशासनिक कार्यों में सरकारी नियंत्रण कम होने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से आम जनता को लाभ मिलता है। हालांकि, कोई भी देश पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर नहीं चल सकता। समस्या तब पैदा होती है जब यह नियंत्रण आवश्यकता से अधिक हो जाता है। भारत में सरकारी नियंत्रण कम करने की बातें तो लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके अनुरूप ठोस बदलाव अपेक्षित गति से नहीं दिखते। यही कारण है कि पश्चिमी देश अब भी भारत में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की शिकायत करते हैं। विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी यही धारणा है कि कारोबारी सुगमता में सुधार के बावजूद भारत में उद्योग-व्यापार स्थापित करना अभी भी आसान नहीं है। कदम-कदम पर सरकारी अनुमतियों की आवश्यकता निवेशकों को हतोत्साहित करती है। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, फिर भी स्थिति वैसी नहीं बन पाई है, जैसी एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखने वाले देश में होनी चाहिए। इस संदर्भ में राज्य सरकारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी राज्यों का रवैया उद्योग और व्यापार के प्रति समान रूप से अनुकूल नहीं है, जो विकसित भारत के लक्ष्य में बाधा बन रहा है। यह निर्विवाद तथ्य है कि विकसित भारत के लिए कारोबारी सुगमता केवल कागजों पर नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। सरकारी तंत्र को जन समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर और संवेदनशील नजर आना चाहिए, किंतु अधिकांश मामलों में ऐसी तत्परता का अभाव दिखाई देता है। नए वर्ष से यह अपेक्षा की जा रही है कि सुधारों की गति और तेज होगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां प्रगति धीमी रही है। शहरी ढांचे का प्रश्न आज अत्यंत गंभीर हो चुका है। नगर निकायों के कामकाज में अपेक्षित सुधार न होने के कारण शहरी नागरिकों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर आबादी के भारी दबाव में हैं और उनका बुनियादी ढांचा चरमराता जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी हो या पीडब्ल्यूडी, गुणवत्तापूर्ण सड़कें तक नहीं बन पा रही हैं। नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य विभागों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। उनके कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही का स्पष्ट अभाव है, जबकि यह सर्वविदित है कि शहर आर्थिक विकास के इंजन होते हैं। समस्या केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं है। निजी उद्योग-व्यापार जगत में भी गुणवत्ता और उत्पादकता की अनदेखी देखने को मिलती है। भारत के बहुत कम उत्पाद विश्वस्तरीय गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं। जब सरकारी कार्य ही दोयम दर्जे के होंगे, तो उनका दुष्प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता और नियामक है। जुगाड़ संस्कृति को बढ़ावा देकर गुणवत्ता आधारित विकास संभव नहीं है। सरकारी क्षेत्र में वास्तविक बदलाव तभी आएगा, जब नौकरशाही की सोच और कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन होगा। दुर्भाग्य से फिलहाल यह सुधार सरकार के प्राथमिक एजेंडे में स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करना होगा।

स्वच्छता में अव्वल, पानी में ज़हर

स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार देश का नंबर-वन शहर घोषित होने वाला इंदौर आज एक भयावह विरोधाभास का प्रतीक बन गया है। जिस शहर को सफाई, प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं का मॉडल बताकर पूरे देश के सामने पेश किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल ने कई जिंदगियां लील लीं। यह घटना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता है, जो रैंकिंग और प्रचार में तो अव्वल है, लेकिन नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की सुरक्षा में फिसड्डी साबित हो रही है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़े और 200 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कई परिवारों के लिए यह बीमारी मौत में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की गुणवत्ता को लेकर वे लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। नलों से बदबूदार और गंदा पानी आने की बात कही जा रही थी, लेकिन नगर निगम ने न तो समय पर जांच कराई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की। सवाल यह है कि अगर शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता, तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी रोकी नहीं जा सकती थी?इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू मौतों के आंकड़ों को लेकर सामने आया विरोधाभास है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पेयजल से केवल चार मौतों की बात कही गई। वहीं, इंदौर के मेयर सार्वजनिक रूप से 10 मौतों की पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर, कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार मृतकों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों का यह भ्रम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह बहस कि कितनी मौतें हुईं, दरअसल इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब भी सच्चाई स्वीकार करने के बजाय उसे कम करके दिखाने में लगा है। यह विडंबना ही है कि एक तरफ स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर की चमक-दमक दिखाई जाती है और दूसरी तरफ अदालत को हस्तक्षेप कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश देना पड़ता है। हाई कोर्ट का दखल इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालतें अंतिम उपाय होती हैं, न कि रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देने वाली संस्था। अगर लोगों को साफ पानी के लिए भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो यह शासन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। घटना के बाद राज्य सरकार ने कुछ प्रशासनिक कदम जरूर उठाए हैं। नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया गया और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। लेकिन क्या यही पर्याप्त कार्रवाई है? ऐसे कदम अक्सर "रूटीन" प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। न तो इससे सिस्टम की खामियां दूर होती हैं और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकती है। असली जरूरत है जवाबदेही तय करने की—यह स्पष्ट करने की कि आखिर किस स्तर पर लापरवाही हुई और किसकी वजह से लोगों की जान गई। दूषित पेयजल से एक भी मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक होनी चाहिए। यहां तो बात कई मौतों और सैकड़ों बीमार लोगों की है। इसके बावजूद अगर पूरा तंत्र आंकड़ों की बाजीगरी में उलझा रहे, तो यह पीड़ितों और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ऊपर से नीचे तक—पानी की आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य विभाग और नगर प्रशासन—सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इंदौर की यह घटना केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। यह देश में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की बदहाली को उजागर करती है। सरकारी और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर एक लाख की आबादी पर औसतन लगभग 35 लोगों की मौत दूषित पेयजल के कारण होती है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत से करीब तीन गुना अधिक है। इसका मतलब साफ है कि हम विकास और रैंकिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पानी जैसी मूलभूत जरूरत को सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए हैं, जिनके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक टैप वॉटर पहुंच चुका है। यह उपलब्धि अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि उस पानी की गुणवत्ता कैसी है? केवल नल लगा देना ही पर्याप्त नहीं, जब तक उसमें से निकलने वाला पानी पीने योग्य न हो। इंदौर की घटना बताती है कि शहरी इलाकों में भी पानी की गुणवत्ता की निगरानी कितनी कमजोर है। भविष्य की तस्वीर और भी चुनौतीपूर्ण है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विकास की यह यात्रा तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। बढ़ती आबादी के साथ पानी के संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा। अगर अभी से ठोस जल प्रबंधन, पाइपलाइन रखरखाव, नियमित जांच और पारदर्शी रिपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई, तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इंदौर की त्रासदी एक चेतावनी है—केवल पुरस्कार, रैंकिंग और ब्रांडिंग से शहर "स्मार्ट" या "स्वच्छ" नहीं बनते। असली कसौटी यह है कि संकट के समय प्रशासन कितना संवेदनशील और जिम्मेदार है। जरूरत है कि स्वच्छता के साथ-साथ जल की गुणवत्ता को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाए। पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी तंत्र के बिना स्वच्छ भारत का सपना अधूरा ही रहेगा। जब तक हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होगा, तब तक किसी भी शहर की नंबर-वन रैंकिंग खोखली ही मानी जाएगी। इंदौर की घटना हमें याद दिलाती है कि विकास का असली पैमाना चमकदार आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी है।

जीवन मंत्र

गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें परिस्थितियाँ, समय और दूसरों की भूमिका भी शामिल होती है। ऐसे में फल को लेकर अत्यधिक चिंता करना व्यर्थ है।

"कर्म करो, फल की चिंता मत करो"

कर्म करो, फल की चिंता मत करो -यह वाक्य भारतीय दर्शन का एक अमूल्य सूत्र है, जो श्रीमद्भगवद्गीता से उद्धृत है। इसका आशय यह नहीं है कि मनुष्य अपने कार्यों के परिणामों के प्रति उदासीन हो जाए, बल्कि यह कि वह अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करे, बिना इस चिंता में डूबे कि उसे बदले में क्या मिलेगा। यह विचार जीवन को तनावमुक्त, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में अधिकांश लोग सफलता, धन, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की अपेक्षा में कार्य करते हैं। यही अपेक्षाएँ अक्सर निराशा, भय और असंतोष को जन्म देती हैं। जब फल हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलता, तो हम हताश हो जाते हैं। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें परिस्थितियाँ, समय और दूसरों की भूमिका भी शामिल होती है। ऐसे में फल को लेकर अत्यधिक चिंता करना व्यर्थ है। कर्मयोग का यह सिद्धांत व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम पूरी एकाग्रता से अपना काम करते हैं, तो हमारा मन परिणाम की चिंता से मुक्त रहता है और कार्य की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाती है। एक छात्र यदि केवल अच्छे अंक की चिंता करे, तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। लेकिन यदि वह सीखने के आनंद के लिए अध्ययन करे, तो सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र नौकरी, व्यापार, कला और समाज सेवा—में समान रूप से लागू होता है। "कर्म करो, फल की चिंता मत करो" का यह भी अर्थ है कि हमें सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति फल से आसक्त नहीं होता, तो अहंकार और निराशा दोनों से बचा रहता है। सफलता मिलने पर वह घमंड में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर टूटता नहीं। यह समभाव ही मानसिक शांति का मूल है। इस विचार का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। यदि हर व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, तो समाज स्वतः ही बेहतर बन सकता है। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, एक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से उपचार करे, एक पत्रकार सत्य को प्राथमिकता दे तो परिणामस्वरूप समाज में विश्वास और नैतिकता का विकास होगा।

शख्सियत | दीपिका पादुकोण

सिनेमा में मेहनत से शिखर तक

दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। उनका जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपनहेगन, डेनमार्क में हुआ। उनके पिता प्रकाश पादुकोण विश्वप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं।

दीपिका का पालन-पोषण बेंगलुरु में हुआ, जहाँ से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। कॉलेज के दिनों में अपने लंबे कद, आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के कारण उन्होंने मॉडलिंग को करियर के रूप में चुना। जल्द ही वे लिरिल, लिम्का, डाबर, क्लोज-अप जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनीं। उन्हें किंगफिशर फैशन अवॉर्ड में 'मॉडल ऑफ द ईयर' का खिताब मिला और वे किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड एंबेसडर भी रहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेबिलिन का चेहरा बनना उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। मॉडलिंग में सफलता के बाद दीपिका ने अभिनय की ओर रुख किया। उनका पहला अभिनय अनुभव हिमेश रेशमिया के म्यूज़िक वीडियो "नाम है तेरा" से हुआ। वर्ष 2006 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्हें असली पहचान 2007 में शाहरुख खान के साथ फराह खान निर्देशित सुपरहिट फिल्म 'ओम शांति ओम' से मिली। इस फिल्म में उनके दोहरे किरदार—शांतिप्रिया और सैंडी—को दर्शकों ने खूब सराहा और उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार मिला। इसके बाद दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'लव आज कल', 'कॉकटेल', 'ये जवानी है दीवानी', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'रामलीला', 'पीकू', 'तमाशा' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों में उन्होंने सशक्त और विविध भूमिकाएँ निभाईं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों-'रामलीला', 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' में उनका अभिनय विशेष रूप से सराहा गया। दीपिका ने 'छपाक' जैसी संवेदनशील फिल्म में एसिड अटैक पीड़िता की भूमिका निभाकर यह साबित किया कि वे केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं। हाल के वर्षों में 'पठान', 'जवान' और 'फाइटर' जैसी बड़ी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने बॉक्स ऑफिस पर भी उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाया। व्यक्तिगत जीवन में दीपिका ने 2018 में अभिनेता रणवीर सिंह से विवाह किया। वे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी जानी जाती हैं और इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर, दीपिका पादुकोण आधुनिक भारतीय सिनेमा की एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जीवन ऊर्जा

जॉन फोर्ब्स नैश का जन्म 5 जनवरी 1928 को अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ। उन्हें आधुनिक गणित और अर्थशास्त्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है। नैश ने गेम थ्योरी के क्षेत्र में काम किया, जिसने दिखाया कि कैसे हर व्यक्ति का निर्णय दूसरों के निर्णयों से प्रभावित होता है।

जॉन नैश: जन्म 5 जनवरी 1928 | जन्म

गणित का जीनियस और साहस का प्रतीक

जॉन फोर्ब्स नैश का यह सिद्धांत आज राजनीति, समाजशास्त्र, व्यापार और आर्थिक नीतियों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नैश का यह योगदान उन्हें विश्वभर में महान गणितज्ञों में स्थापित करता है। जॉन नैश का जीवन केवल प्रतिभा और उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग था, जिसने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गहरी चुनौतियां पैदा कीं। इसके बावजूद, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने ज्ञान और गणितीय अनुसंधान में लगे रहे। उनके जीवन की यह संघर्षपूर्ण यात्रा दर्शाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और आत्मविश्वास से असाधारण सफलता पाई जा सकती है। नैश की कहानी प्रेरक इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में न केवल पुरस्कार और ख्याति हासिल की, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और लगन बनाए रखना संभव है। 1994 में उन्हें उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी प्रेरक जीवन कहानी को 2001 में फिल्म ₹ए ब्यूटीफुल माइंड₹ के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाया गया, जिसने उनके संघर्ष और सफलता को उजागर किया। जॉन नैश का जीवन

हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल पुरस्कार और ख्याति में नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ, धैर्य और दूसरों के साथ सहयोग में है। उनके कार्य और दृष्टिकोण आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह उद्धरण जॉन नैश के जीवन और दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि असली महानता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और ज्ञान की गहराई में होती है। "मैं हमेशा सोचता रहा कि जीवन और गणित में असली सुंदरता संतुलन और समझ में है, केवल जीत और पुरस्कार में नहीं।"

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

धर्म-अधर्म का विवेकपूर्ण और परिस्थितिसापेक्ष स्वरूप

धर्म और अधर्म को सामान्यतः हम कठोर नियमों की तरह देखते हैं, किंतु भारतीय दर्शन में यह अवधारणा अत्यंत सूक्ष्म, विवेकपूर्ण और परिस्थितिनिष्ठ है। धर्म केवल कर्म का बाह्य स्वरूप नहीं, बल्कि उसके पीछे निहित उद्देश्य, भावना और परिणाम से जुड़ा होता है। इसी कारण किसी विशेष परिस्थिति में किया गया अधर्म भी धर्म के समान माना जा सकता है और कभी-कभी बाहरी रूप से धर्म प्रतीत होने वाला कर्म अधर्म बन जाता है।

झूठ बोलना सामान्य रूप से अधर्म कहा गया है, क्योंकि यह विश्वास और सत्य को नष्ट करता है। किंतु यदि झूठ बोलने से किसी निर्दोष प्राणी का जीवन बचता है, किसी बच्चे या निर्बल की रक्षा होती है, तो वही झूठ धर्म का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत सत्य बोलना धर्म है, परंतु यदि सत्य के कारण किसी धार्मिक, निर्दोष और निःशस्त्र व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाए, तो वह सत्य अधर्म बन जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म का मूल्यांकन केवल कथन से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से किया जाना चाहिए।

चोरी करना अधर्म है, पर यदि चोरी किसी कुटुंब, समाज या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए की जाए, और उसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि व्यापक कल्याण हो, तो वही कर्म धर्म कहलाता है। इसी प्रकार जीव-हत्या को अधर्म कहा गया है, किंतु यदि एक जीव की हत्या से अनेक निर्दोष प्राणियों की रक्षा संभव हो, तो वह कर्म करुणा और संतुलन के कारण धर्म बन जाता है। दान देना धर्म है, लेकिन दान यदि पापियों, अत्याचारियों या अधर्मी शक्तियों को दिया जाए, जिससे वे और अधिक विनाश फैलाएँ, तो ऐसा दान अधर्म बन जाता है। इसी तरह हिंसा और हत्या को अधर्म माना गया है, किंतु बच्चों, महिलाओं, अपने कुल-कुटुंब, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा, यदि अंतिम विकल्प हो, तो वह मर्यादा-रक्षा का धर्म बन जाती है।

"पृथ्वी कुटुंब के समान है" यह एक महान धर्मवाक्य है, परंतु यदि पृथ्वी के संतुलन के लिए कोई कुटुंब या समूह निरंतर विनाशकारी बन जाए, तो उस विनाशकारी तत्व का अंत करना भी धर्म माना जाएगा। विष पिलाना और मादक पदार्थों का सेवन अधर्म है, किंतु यदि विष या मादक पदार्थों के प्रयोग से किसी निर्दोष प्राणी की रक्षा होती है, तो उसका उद्देश्य धर्ममय हो जाता है। वास्तव में धर्म का अर्थ है प्राणियों और प्रकृति के मध्य संतुलन बनाए रखने वाले नियमों का पालन। अधर्म तब धर्म का रूप धारण करता है, जब उसका उद्देश्य दया, क्षमा, समता, अहिंसा और प्राणियों का कल्याण हो। जहाँ धर्म है, वहीं जय है। नशा और जुआ दोनों मतिमार हैं, ये मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अभोज्य और अशुद्ध भोजन का सेवन करने से आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य धर्म और अधर्म में अंतर अपनी विवेक शक्ति से करे और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे। इनके अध्ययन से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है तथा जीवन के क्लेश दूर होते हैं।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

'जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया है कि अगर सीपीआई (एम) और भाजपा एक साथ भी आ जाएं, तो भी हम उनका सामना कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव की जीत से कांग्रेस नेताओं को और विनम्र होना चाहिए।

-केसी वेणुगोपाल
आईसीसी महासचिव

'आने वाले चुनावों में, भाजपा, एआईएडीएमके और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और डीएमके को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रही है। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में है।'

-अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री

'सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत में नफरत का माहौल बना दिया है... न्यायाधीशों ने जो किया है वह गलत है, उन्होंने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है: एक हिस्सा नफरत करता है तो दूसरा प्यार करता है। इसके जरिए उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है।

-मेनका गांधी
बीजेपी नेता

6 चुनाव से पहले वे 'सोनार बांग्ला' का वादा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों की पिटाई करते हैं। लोग पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे।
की मुख्यमंत्री

-ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

वाशिम में जानलेवा चाइनीज मांझा बना खतरा, बाइक सवार की गर्दन गंभीर रूप से घायल

वाशिम: जिले के शिरपुर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की गर्दन गंभीर रूप से घायल हो गई। समय पर सतर्कता बरतने से उसकी जान बच गई, लेकिन घटना ने एक बार फिर चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिरपुर निवासी खैरू बुद्धू चौधरी (57) बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान खंडोबा मंदिर के पास सड़क पर लटक रहे चाइनीज मांझे से उनका गला कट गया। अचानक हुए इस हादसे में चौधरी ने तुरंत बाइक रोक दी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि, उनके गले पर गहरा घाव आया है। घटना के बाद घायल अवस्था में चौधरी ने शिरपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मकर संक्रांति से पहले इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी से क्षेत्र में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके।

दोपहिया वाहन पर पलटा ट्रक, दो की मौत

नासिक । महाराष्ट्र के नासिक जिले के नासिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर त्र्यंबकेश्वर गेस्ट हाउस के पास रविवार को दोपहर पत्थरों से लदा एक ट्रक अचानक दोपहिया वाहन पर पलट गया। इस हादसे दो लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया और इसके नीचे से दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज दोपहर में बुलढाणा जिले के शिवम राजेश उबरहांडे (22) और भूमिका समाधान खेडेकर (21) दोपहिया वाहन से नासिक की ओर आ रहे थे। उनका वाहन जैसे ही त्र्यंबकेश्वर गेस्टहाउस के पास ढलान से गुजर रहा था। उसी समय एक ट्रक सिलेंडर भरे अन्य ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में शिवम और भूमिका की मौके पर मौत हो गई।

बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार पर भाजपा का तीखा हमला

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए बीएमसी में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुंबई भाजपा अध्यक्ष व विधायक अमित साटम ने रविवार को एक विस्तृत आरोप-पत्र जारी कर दावा किया कि बीते 25 वर्षों में बीएमसी के कामकाज के दौरान करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का कथित घोटाला हुआ है। उन्होंने इसे "देश का सबसे बड़ा नगर निकाय घोटाला" बताया। अमित साटम ने कहा कि मुंबईकर अब सब समझ चुके हैं और जिन्होंने वर्षों तक जनता की मेहनत की कमाई से अपनी तिजोरियां भरी हैं, उन्हें इस चुनाव में जवाब मिलेगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर शहर के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को नुकसान पहुंचाया गया।भाजपा के मुताबिक, सड़कों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद गड्ढों की समस्या बनी रही। आरोप-पत्र में कहा गया है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और ऊंची दरों पर काम आवंटित कर सरकारी धन की बर्बादी की गई। कोविड-19 अवधि को लेकर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए। साटम ने इसे "कफन चोरी जैसा अपराध" बताते हुए कहा कि उस दौरान करीब 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले हुए। नियमों को दरकिनार कर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े ठेके दिए गए। बॉडी बैग घोटाला: 1,500 रुपये की बॉडी बैग 6,721 रुपये में खरीदी गई। ऑक्सीजन प्लांट मामला: 320 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद मृत्यु दर अधिक रहने का दावा।

मुख्य चुनाव पर्यवेक्षकों ने किया मीडिया मॉनिटरिंग सेल और शिकायत निवारण कक्ष का निरीक्षण

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में चुनाव से जुड़ी प्रत्येक जिम्मेदारी विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में सौंपी गई है।

शिकायत निवारण कक्ष की व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नागरिकों की चुनाव संबंधी शिकायतों और सुझावों के लिए नवी मुंबई मनपा मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की गई है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800 222 309 पर संपर्क कर सकते हैं या nmmcelectionobserver@gmail.com ई-मेल आईडी पर आदर्श आचार संहिता अथवा अन्य चुनावी विषयों से जुड़ी शिकायतें और सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा, मनपा मुख्यालय स्थित चुनाव विभाग में लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक ने आयुक्त के साथ शिकायत निवारण कक्ष का निरीक्षण कर वहां मौजूद रिकॉर्ड की जांच की और प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का नियमित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।

मीडिया मॉनिटरिंग सेल का भी निरीक्षण

मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक ने मनपा मुख्यालय के तीसरे माले पर स्थापित मीडिया मॉनिटरिंग सेल का भी दौरा किया। यहां उपग्रह और केबल चैनलों पर प्रसारित समाचारों की निगरानी के लिए टेलीविजन सेट लगाए गए हैं। नियुक्त कर्मचारियों द्वारा समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रकाशित नवी मुंबई मनपा चुनाव से संबंधित खबरों की नियमित निगरानी की जा रही है। दैनिक समाचार पत्रों की चुनावी खबरों की कतरनों को भी संकलित किया जा रहा है।

राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज पर सख्त नजर

मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक ने निर्देश दिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले चुनावी विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले महानगरपालिका स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही पेड न्यूज से जुड़े मामलों पर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप संपन्न हों।

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडल के प्रबंध निदेशक डॉ. भाऊसाहेब दांगड़े को मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय सावळकर को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों पर्यवेक्षकों ने विशेष बैठकों के माध्यम से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की चरणबद्ध समीक्षा की और चुनाव को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी निर्वाचन निर्णय अधिकारियों के कार्यालयों का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों की प्रत्यक्ष जांच भी की।

बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस–वंचित तालमेल में दरार

गठबंधन के बावजूद मुंबई के 5 वार्डों में आमने सामने होंगे उम्मीदवार

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच बने गठबंधन को झटका लगा है। सीटों के तालमेल के बावजूद वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई के पांच वार्डों में 'मैत्रीपूर्ण मुकाबला' लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से इन वार्डों में कांग्रेस को सीधी चुनौती मिलेगी और मतों के बंटवारे की संभावना बढ़ गई है, जिससे चुनावी गणित और ज्यादा दिलचस्प हो गया है।

सीट बंटवारे के बाद बदले सुर

15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। समझौते के तहत कांग्रेस ने वंचित को 62 सीटें देने पर सहमति जताई थी। बाद में वंचित ने करीब 12 सीटें कांग्रेस को लौटाने की घोषणा की, जिससे वह लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गई।

नामांकन वापसी नहीं, मुकाबला तय

यह उम्मीद जताई जा रही थी कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन वंचित इन वार्डों से अपने उम्मीदवार वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी पांच वार्डों में उम्मीदवार बनाए रखने से साफ हो गया है कि यहां कांग्रेस और वंचित के बीच सीधा मुकाबला होगा।

इन वार्डों में होगी टक्कर

वार्ड 140 (मानखुर्द–शिवाजीनगर, एससी आरक्षित) : कांग्रेस ने सांसद चंद्रकांत हंडोरे की बेटी को मैदान में उतारा है, जबकि वंचित ने सोहन सदामस्त को टिकट दिया है। दलित मतदाताओं की संख्या अधिक होने से मुकाबला अहम माना जा रहा है।

वार्ड 116 (भांडुप) : कांग्रेस की संगीता तुलसकर के सामने वंचित की राजकन्या सरदार।

वार्ड 133 : कांग्रेस ने यह सीट राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन वंचित ने यहां सुप्रिया जाधव को उम्मीदवार बनाया है।

मराठी भाषा हमारी पहचान है, हिंदी की कोई जबरदस्ती नहीं : उपमुख्यमंत्री

डीबीडी संवाददाता । सातारा

साता ात आयोजित 99वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन का समारोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मराठी भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मराठी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी भाषा की कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान और गौरव बढ़ाया जाएगा।

मराठी भाषा का गौरव और इतिहास

एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण की शुरुआत राजमाता येसूबाई, सातारा शहर के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज की स्मृति को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा, 'सातारा छत्रपती शिवाजी महाराज के स्वराज्य की पवित्र भूमि है। ऐसे स्थान पर साहित्य संमेलन का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है। यह केवल साहित्यिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मराठी भाषा और संस्कृति का उत्सव है।'उन्होने कहा कि मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना वर्षों की तपस्या का फल है और उनके मुख्यमंत्री पद के दौरान मायमराठी को यह सम्मान मिला, जिसे वह कभी नहीं भूल सकते।

सरकार की पहल और योजनाएं

उपमुख्यमंत्री ने मराठी भाषा और साहित्य के विकास के लिए सरकार की पहल का जिक्र किया। अमरावती के रिद्धपूर में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में 150 करोड़ की लागत से मराठी भाषा भवन,लंदन में छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र,दिल्ली में कुसुमाग्रज अध्ययन केंद्र,दुनिया के 75 देशों में अंतरराष्ट्रीय मराठी मंच।

राज्यगीत "जय जय महाराष्ट्र माझा" को मान्यता

साहित्य संमेलन के लिए अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है, और सातारा साहित्य संमेलन के लिए 3 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। शिंदे ने घोषणा की कि पुस्तक स्टॉल के लिए सवलत, ग्रंथालय निर्माण, डिजिटल वाचन सुविधाओं के लिए कोट्यवधी का निधि और लेखन व प्रकाशन व्यवसाय पर 18% जीएसटी कटौती के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा,'मराठी केवल भाषा नहीं, हमारी अस्मिता है। इसे संरक्षित किया जाए, तभी मराठी माणूस टिकेगा। भाषा जात-धर्म से परे लोगों को जोड़ती है।'

समापन और अभिनंदन

अंत में उन्होंने संत तुकाराम महाराज के "शब्दांचीच रत्ने" उद्धरण के साथ मराठी भाषा की परंपरा बनाए रखने का आवाहन किया। उन्होंने आयोजन समिति, अध्यक्ष और सभी साहित्य प्रेमियों को ससम्मान अभिनंदन किया। समारोप समारोह में उपस्थिति: सहकार और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री महेश शिंदे, साहित्यिक विश्वास पाटील, गुजरात से पद्मश्री विजेता रघुवीर चौधरी, मराठी साहित्य महामंडळ अध्यक्ष मिलिंद जोशी, और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

टीएमसी ने पुनः उपयोग किए गए पानी से ठाणे स्टेशन परिसर में चलाया विशेष सफाई अभियान

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर में व्यापक स्तर पर 'डीप क्लीन ड्राइव' चलाया। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए यह विशेष सफाई अभियान ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। शुक्रवार रात शुरू हुए इस अभियान का असर शनिवार सुबह साफ नजर आया, जब स्टेशन से गुजरने वाले यात्रियों ने क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर मनपा की सराहना की।

स्टेशन परिसर और सेटिस ब्रिज की पानी से धुलाई

शुक्रवार रात ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर, सेटिस सेतु सहित आसपास के पूरे क्षेत्र को पानी से धोकर साफ किया गया। मनपा उपायुक्त मधुकर बोडके ने बताया कि इस अभियान की खास बात यह रही कि कोपरी स्थित एसटीपी प्रोजेक्ट से प्रोसेस किया गया, दोबारा इस्तेमाल के योग्य पानी उपयोग में लाया गया, जिससे जल संरक्षण का भी संदेश दिया गया। इस बड़े सफाई अभियान में ठाणे मनपा प्रशासन के साथ टीएमसी परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अतिक्रमण विभाग, शहर यातायात पुलिस, रेलवे प्रशासन, जल आपूर्ति विभाग, पार्क्स और शिक्षा विभाग सहित कई एजेंसियों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

अधिकारियों ने भी लिया अभियान में हिस्सा

अभियान के दौरान यातायात शाखा के उपायुक्त पुलिस पंकज शिरसाट, टीएमटी मैनेजर भालचंद्र बेहरे, ट्रैफिक ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रानी शिंदे, पंजाबराव कवले और सैनिटेशन इंस्पेक्टर लक्ष्मण पुरी भी मौके पर मौजूद रहे और सफाई कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर सभी ने स्वच्छता की शपथ लेकर ठाणे शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प भी लिया। इस डीप क्लीन ड्राइव के बाद स्टेशन क्षेत्र नागरिकों के लिए अधिक साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक बन गया है। मनपा प्रशासन ने अपील की है कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर ठाणेवासी का कर्तव्य भी है, ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखा जा सके।

चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र सुविधा

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में शासकीय और अर्ध-शासकीय कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी का मतदाता के रूप में मतदान का अधिकार प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में लागू की गई है।

चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा

नवी मुंबई महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के लिए रायगढ़ जिले की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ-साथ नवी मुंबई स्थित सिडको, अन्य शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालयों और निजी स्कूलों के कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे कर्मचारी जो नवी मुंबई के मतदाता हैं लेकिन चुनाव कार्य में तैनात होने के कारण मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष डाक मतपत्र सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में नोडल अधिकारी एवं उप आयुक्त स्मिता काले ने जानकारी दी कि नवी मुंबई महानगरपालिका के सभी आठ निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालयों में विशेष पोस्टल बैलेट सहायता कक्ष स्थापित किए गए हैं।

पांच दिनों तक मिलेगा मार्गदर्शन

कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान में सहायता देने के लिए आठों निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालयों में विशेष सहायता कक्ष बनाए गए हैं। यहां 8, 9, 10, 11 और 12 जनवरी 2026 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर डाक मतदान से संबंधित मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय स्तर पर भी एक विशेष पोस्टल बैलेट सहायता कक्ष स्थापित किया गया है। किसी भी जानकारी या समस्या के लिए कार्यालयीन समय में 9819452487 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही nmmcpostalballot@gmail.com ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। चुनाव प्रक्रिया में समन्वय बनाए रखने के लिए मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं के आयुक्तों को पत्र लिखकर यह जानकारी देने को कहा है कि नवी मुंबई के मतदाता, जो उनके यहां चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं, वे डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकें।

8 जनवरी को करना होगा आवेदन

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत अधिकारी और कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अंतिम मतदाता सूची में जांचने के बाद, जिस प्रभाग में उनका नाम दर्ज है, वहां के निर्वाचन निर्णय अधिकारी के पास 8 जनवरी 2026 को प्रपत्र पीबी-1 के माध्यम से आवेदन कर डाक मतपत्र की मांग कर सकते हैं। आवेदन के साथ चुनाव ड्यूटी पर नियुक्ति का आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को डाक मतपत्र प्रदान किया जाएगा। मतदाता को पीबी-7 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मतपत्र पर मतदान कर, निर्धारित प्रक्रिया के तहत बंद लिफाफे में उसे वापस निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष सुख के साधन जुटेंगे। भूमि व भवन की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। संतान की प्रगति होगी। व्यापार-व्यवसाय में प्रगतिकारक वातावरण का सृजन होगा। पारिवारिक स्थिति आनंददायक रहेगी। मन प्रफुल्लित रहेगा।

वृष विवाद व जल्दबाजी से बचें। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अधूरे काम समय से पूरे होने के योग हैं। नए कार्यों से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन का संग्रह होगा।

मिथुन तीर्थयात्रा हो सकती है। सत्संग का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिन अच्छा होने की संभावना है। प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। परिवार में मेल-मिलाप बढ़ेगा।

कर्क संतान पक्ष की चिंता रहेगी। चोट व दुर्घटना से बचें। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। खर्च का बोझ बढ़ेगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। व्यापार, नौकरी में अड़चनें आने से मनोबल में कमी आ सकती है।

सिंह प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रयास सफल रहेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी। मान-सम्मान मिलेगा। धनार्जन होगा। प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सुख एवं पत्नी के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी से बहस न करें।

कन्या लेनदारी वसूल होगी। यात्रा मनोरंजक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है। आर्थिक उन्नति होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी।

तुला प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। बाहर सहायता से काम होंगे। प्रसन्नता रहेगी। संतान के संबंध में संतोष रहेगा। व्यावसायिक अथवा आजीविका संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। पुरुषार्थ का पूर्ण फल मिलेगा। थकान रहेगी। शत्रु भय रहेगा।

वृश्चिक यात्रा में सावधानी रखें। विवाद को बढ़ावा न दें। दु:खद समाचार मिल सकता है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी पर संयम रखें। विरोधियों से सावधान रहें। परिवार की परेशानी का हल संभव है। भागीदारी के कामों में सफलता मिलेगी।

धनु अतिथियों का आवागमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। आत्मसम्मान बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। पारिवारिक सुख-शांति बरकरार रहेगी। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। यात्रा होगी।

मकर कुसंगति से बचें। फालतू खर्च होंगे। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी। कामकाज का बोझ बढ़ने से व्यापार पर विपरीत असर हो सकता है। वाद-विवाद से दूर रहें।

कुंभ घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। रुके कार्यों में गति आएगी। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक। पुराने रुके कामों, लेनदेन में सफलता की संभावना है। रोमांस में सफलता मिलेगी।

मीन अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जोखिम उठाएं। यात्रा मनोरंजक रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। धनार्जन होगा। सोच-समझकर कार्य करना लाभप्रद रहेगा। पुरुषार्थ सफल होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। व्यापार में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे।

जन्मपत्री में मोती रत्न: चंद्र ग्रह के अनुसार लाभ, हानि और वैज्ञानिक–ज्योतिषीय विवेचन

प्रियंका जैन
9769994439

सादगी, पवित्रता और कोमलता का प्रतीक माने जाने वाला मोती केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह का सजीव प्रतिनिधि माना जाता है। इसे मुक्ता, शशि रत्न, शीशा रत्न और अंग्रेज़ी में पर्ल कहा जाता है। सामान्यतः लोग मोती को केवल सफेद रंग में जानते हैं, परंतु प्रकृति में यह गुलाबी, क्रीमी, हल्का पीला, लालिमा लिए हुए तथा कभी-कभी नीले आभास के साथ भी पाया जाता है। मोती का जन्म समुद्र के भीतर रहने वाले घोंघे (Oyster) के शरीर में होता है, जहाँ एक विदेशी कण के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जमती जाती हैं और वर्षों बाद एक पूर्ण मोती का निर्माण होता है। यही प्राकृतिक प्रक्रिया इसे अन्य रत्नों से अलग और अधिक संवेदनशील बनाती है।

ज्योतिष के अनुसार मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन, भावना, माता, स्मृति, तरल तत्व, शीतलता और मानसिक संतुलन का कारक ग्रह है। जिन जातकों की जन्मपत्री में चंद्र कमजोर, पीड़ित, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से ग्रसित हो या मानसिक अशांति, भय, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, निर्णय में अस्थिरता जैसी समस्याएँ हों, उनके लिए मोती अत्यंत प्रभावी रत्न माना गया है। विशेष रूप से कर्क राशि, जिसकी स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, उनके लिए मोती धारण करना सर्वाधिक शुभ कहा गया है। कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों में मोती मानसिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।

मोती का प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के जल तत्व को संतुलित करता है। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही दृष्टियों से मोती को शीतल और सौम्य रत्न माना गया है। अनिद्रा, अवसाद, अत्यधिक तनाव, भय, घबराहट, सिरदर्द, नेत्र रोग, हृदय से जुड़ी समस्याएँ तथा महिलाओं में गर्भाशय संबंधी विकारों में मोती का सकारात्मक प्रभाव माना जाता है। जिन लोगों को बार-बार भावनात्मक टूटन, अकेलापन या असुरक्षा की भावना घेर लेती है, उनके लिए मोती एक प्रकार का मानसिक कवच बनता है।

हालाँकि मोती जितना लाभकारी है, उतना ही सावधानी की माँग भी करता है। यह हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों का स्वामी होकर मारक या बाधक ग्रह बन गया हो, या जिनकी राशि व लग्न में चंद्र अशुभ भावों का अधिपति हो, उनके लिए मोती हानि भी पहुँचा सकता है। ऐसे मामलों में मोती पहनने से मानसिक भ्रम, निर्णयहीनता, आलस्य, भावुकता की अधिकता और जीवन में स्थिरता की कमी देखी जा सकती है। इसलिए बिना कुंडली परीक्षण के मोती धारण करना उचित नहीं माना जाता, यद्यपि सामान्य मानसिक शांति के लिए अल्प वजन का मोती कुछ लोग धारण करते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से मोती अरैगोनाइट नामक खनिज से बना होता है, जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। इसके क्रिस्टल विषम अक्षीय होते हैं और यही कारण है कि मोती अत्यंत कोमल रत्न माना जाता है। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार मोती में लगभग 90 से 92 प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट, 4 से 6 प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ और 2 से 4 प्रतिशत जल पाया जाता है।

न्यूज ब्रीफ

कॉलोनाइजर हत्याकांड में एक लाख का इनामिया गिरफ्तार

वाराणसी। वाराणसी में चर्चित कॉलोनाइजर महेन्द्र गौतम हत्याकांड से जुड़े एक लाख रुपये के इनामी शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए बदमाश का करीब एक किलोमीटर तक पीछा किया, जिसके बाद वह पुलिस की गोली से घायल होकर पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरविन्द यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू, निवासी सिमराफैज, कोतवाली गाजीपुर के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि महेन्द्र गौतम की हत्या में शामिल इनामी शूटर अपने एक साथी के साथ सरायमोहना–सलारपुर क्षेत्र में गंगा किनारे मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध नजर आए, जिन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और 750 रुपये नकद बरामद किए हैं। डीसीपी ने बताया कि इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। घायल आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, वहीं फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई में सारनाथ थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, एसओजी प्रभारी गौरव सिंह, चौकी प्रभारी राहुल यादव, सरायमोहना चौकी इंचार्ज अनुज शुक्ला सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार शूटर कुख्यात अपराधी बनारसी यादव का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस भर्ती में मिले तीन साल की छूट : चंद्रशेखर

लखनऊ। भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चन्द्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट देने की मांग की है। सांसद चन्द्रशेखर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पिछले कई वर्षों में भर्तियों में अत्यधिक विलम्ब,परीक्षाओं का स्थगन तथा प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रभावित होती रही है। इसके लिए अभ्यर्थी किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं। हजारों योग्य एवं शारीरिक रूप से सक्षम युवा केवल आयु सीमा के कारण पुलिस सेवा में अवसर से वंचित हो रहे हैं। भीम आर्मी चीफ ने मांग की है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कम से कम तीन वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाय ताकि प्रशासनिक देरी का खामियाजा युवाओं को न भुगतना पड़े।

ज्ञान, संस्कृति और प्रतिभाओं का संगम है बनारस: नरेंद्र मोदी

एजेंसी । वाराणसी

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया वर्चुअल शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत की विकास यात्रा की सराहना हो रही है और इसका प्रभाव खेल जगत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से जुड़े इस वर्चुअल समारोह में देशभर से आए एक हजार से अधिक खिलाड़ी और कोच शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के मेजबान के रूप में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल केवल शारीरिक कौशल का खेल नहीं, बल्कि आपसी तालमेल, संतुलन और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह खेल टीम भावना को मजबूत करता है, जहां हर खिलाड़ी 'टीम फर्स्ट' के सिद्धांत के साथ मैदान में उतरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार एक टीम विश्वास, समन्वय और तत्परता के बल पर जीत हासिल करती है, उसी तरह देश भी सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता अभियान से लेकर डिजिटल भुगतान, 'एक पेड़ मां के नाम' से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक—हर क्षेत्र में नागरिकों की सहभागिता भारत की प्रगति का आधार बन रही है। संबोधन की शुरुआत 'नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव' के जयघोष से करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक क्षेत्र सुधारों की गति से आगे बढ़ रहा है और खेल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 जैसे कदमों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और युवा खिलाड़ी शिक्षा व खेल दोनों क्षेत्रों में संतुलित प्रगति कर सकेंगे।

कुश्ती, मुक्केबाजी काशी की पहचान

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी को काशी के खेल मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इससे पहले जी-20 बैठकों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रवासी भारतीय सम्मेलनों जैसे आयोजनों ने भी वाराणसी को वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने काशी की खेल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह शहर सदियों से ज्ञान, संस्कृति और खेल प्रतिभाओं का केंद्र रहा है। बीएचयू, यूपी कॉलेज और काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों से निकले खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। कुश्ती, मुक्केबाजी, नौकायन और कबड्डी जैसे खेलों की समृद्ध परंपरा काशी की पहचान का हिस्सा रही है।

28 राज्यों की टीमें, एक हजार खिलाड़ी

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमों की भागीदारी इस प्रतियोगिता को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की जीवंत तस्वीर बनाती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह चैंपियनशिप काशी की सांस्कृतिक उपलब्धियों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। उल्लेखनीय है कि 4 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर की 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें एक हजार से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महापौर अशोक तिवारी, जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल फेडरेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

उत्तरकाशी: बिना बर्फबारी के जम गईं नदियां

गंगोत्री में पारा माइनस में, नदियों-नालों में जमी कई इंच मोटी बर्फ

बर्फबारी न होने से सेब उत्पादकों और काश्तकारों की चिंता बढ़ी

एजेंसी । देहरादून

उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम में इस शीतकाल में अब तक हिमपात नहीं हुआ है, लेकिन अत्यधिक ठंड ने पूरे क्षेत्र को जमा दिया है। हालात ऐसे हैं कि साल भर बहने वाली छोटी-बड़ी नदियां और नाले कई इंच मोटे पाले की परत में बदल चुके हैं और पानी का प्रवाह लगभग थम सा गया है। क्षेत्र में तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है और रात के समय यह माइनस 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। बर्फबारी न होने से सेब उत्पादकों और स्थानीय काश्तकारों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका सीधा असर आगामी फसल पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कनखू बैरियर प्रभारी राजवीर रावत ने बताया कि इस मौसम में गंगोत्री और गोमुख ट्रैक पर स्थित सभी नदी-नाले कड़ाके की ठंड के चलते पूरी तरह जम चुके हैं। भागीरथी नदी में भी पाले की मोटी परत जमी हुई है, जिससे उसमें पानी का बहाव बेहद कम रह गया है।

कड़ाके की ठंड में 25 साधु साधना में लीन

इसके अलावा केदार गंगा, ऋषिकुर नाला, पागल नाला और चीड़बासा नाला भी पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद गंगोत्री धाम में साधना में लीन करीब 25 साधु मौजूद हैं। साथ ही सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क के छह कर्मचारी, पुलिस के दो जवान और मंदिर समिति के कर्मी तैनात हैं।

सरकारी जमीन से हटाई गई अवैध मस्जिद

संभल में 20 जरूरतमंद परिवारों को मिला आशियाने का अधिकार

सरकारी जमीन पर मस्जिद के अलावा चलाई जा रही थीं दुकानें

संभल। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद कब्जा मुक्त कराई गई भूमि को 20 गरीब एवं बेसहारा पात्र व्यक्तियों के नाम आवंटित कर दिया गया। प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित मस्जिद कमेटी ने स्वयं ही निर्माण को ध्वस्त कर मलबा भी हटवा दिया। इसके उपरांत रविवार को शासन एवं प्रशासन की संयुक्त टीम गांव पहुंची और पूरे प्रकरण की स्थलीय जांच की। इस दौरान सरकारी जमीन पर बने मदरसे और उससे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

धारा 67 के तहत की गई बेदखली की कार्रवाई

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर धारा 67 के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली भूमि पर 1500 वर्ग मीटर में मदरसा निर्मित था, जहां दुकानों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और किराया भी वसूला जा रहा था। इन सभी अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि पर किया गया अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे निर्माणों को हटाया जाना तय है। उन्होंने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि को सामाजिक न्याय के उद्देश्य से 20 निर्धन एवं बेसहारा पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

संडे बाजार बंदी के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद शहर में वर्षों से लगने वाले संडे बाजार को बंद किए जाने के निर्णय से व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी देखने को मिली। रविवार को सैकड़ों व्यापारियों ने इस फैसले के विरोध में नेहरू रोड पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन से प्रतिबंध तत्काल हटाने की मांग की। व्यापारी नेता अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित इस धरने के दौरान कारोबारियों ने प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना था कि संडे बाजार शहर की पुरानी परंपरा है और इससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए व्यापारियों ने सर्दी से जुड़े सामान की खरीद में पहले ही लाखों रुपये का निवेश कर रखा है। अंकुर श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा सुझाया गया वैकल्पिक स्थान—क्रिश्चियन कॉलेज का मैदान—व्यापारियों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह एक निजी ट्रस्ट की संपत्ति है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाजार को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने की सूचना मिलते ही घुमना चौकी प्रभारी अमित गुप्ता सहित मऊ दरवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल आज के लिए बाजार लगाने की अनुमति देते हुए आगे का समाधान उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया।

2.75 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं निर्यातक

मुरादाबाद। देश के निर्यातकों के लिए राहत भरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व एवं पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता योजना को प्रभावी कर दिया गया है। इसके तहत निर्यात ऋण लेने वाले उद्यमों को अब वार्षिक आधार पर 2.75 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत शिपमेंट से पहले और बाद में लिए गए निर्यात ऋण पर यह ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

व्यापार जगत

नए साल की धीमी शुरुआत, तीन कंपनियां आजमाएंगी किस्मत

एसएमई सेगमेंट की हैं तीनों कंपनियां, जनवरी के पहले सप्ताह में सीमित रहे आईपीओ

नई दिल्ली। वर्ष 2026 के आगाज के साथ ही देश के प्राथमिक बाजार में सतर्कता का माहौल दिखाई दे रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में आईपीओ गतिविधियां अपेक्षाकृत सीमित रहने वाली हैं। इस दौरान मेनबोर्ड से केवल एक और एसएमई श्रेणी से तीन कंपनियां पूंजी बाजार में दस्तक देंगी। बाजार विशेषज्ञ इसे साल की शुरुआत में निवेशकों की सामान्य सावधानी से जोड़कर देख रहे हैं। आमतौर पर जनवरी में निवेशक वर्षांत अवकाश के बाद बाजार की दिशा समझने में समय लेते हैं, जिसके चलते नई लिस्टिंग की रफ्तार धीमी रहती है। हालांकि चालू तिमाही के आगे के महीनों में कई बड़े आईपीओ आने की संभावना है, लेकिन कंपनियां फिलहाल निवेशक धारणा को परखने के मूड में नजर आ रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही साल की शुरुआत में आईपीओ बाजार की गति धीमी हो, लेकिन मजबूत घरेलू तरलता और सकारात्मक निवेश माहौल के चलते आने वाले महीनों में प्राथमिक बाजार में रौनक लौटने की संभावना बनी हुई है।

गैबियन टेक्नोलाजी इंडिया का पहला IPO

एसएमई श्रेणी में वर्ष का पहला आईपीओ गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया का होगा, जो 6 से 8 जनवरी तक खुलेगा। कंपनी करीब 29 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए किया जाएगा। यह इश्यू बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा।

यजूर फाइबर्स जुटाएगी 120 करोड़ रुपए

इसी अवधि में यजूर फाइबर्स का आईपीओ भी खुलेगा, जिसका आकार लगभग 120 करोड़ रुपए है। कंपनी जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और वर्किंग कैपिटल के लिए करेगी। यह इश्यू बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होगा।

विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल

वहीं, विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल 7 से 9 जनवरी के बीच फिक्स्ड प्राइस आईपीओ के जरिए लगभग 35 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा जैसे वाहनों के क्षेत्र में सक्रिय है और यह एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी।

FPI ने शुरुआत में ही निकाले 7,600 करोड़ रुपए

नए साल की शुरुआत में विदेशी निवेशक रहे सतर्क

नई दिल्ली। वर्ष 2026 की शुरुआत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एहतियाती रुख अपनाया है। जनवरी के शुरुआती दो कारोबारी सत्रों में ही एफपीआई ने करीब 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी बाजार से बाहर निकाल ली, जिससे बाजार में हल्का दबाव देखने को मिला। यह प्रवृत्ति पिछले वर्ष की तस्वीर से अलग नहीं है। 2025 के दौरान विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड स्तर पर पूंजी निकासी की थी। रुपए की कमजोरी, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिका में संभावित टैरिफ नीतियों ने उस दौरान निवेश धारणा को प्रभावित किया था, जिसका असर सीधे भारतीय बाजारों पर पड़ा। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चालू वर्ष में परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो सकती हैं। निवेश सलाहकारों के अनुसार, भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के बेहतर आय अनुमान विदेशी पूंजी के लिए आकर्षण का कारण बन सकते हैं।

भारत-अमेरिकी व्यापारिक संबंध

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में स्थिरता आती है, वैश्विक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव थमता है और डॉलर-रुपया विनिमय दर संतुलित रहती है, तो विदेशी निवेशकों का भरोसा दोबारा बन सकता है। मौजूदा बाजार मूल्यांकन को भी अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत संतुलित माना जा रहा है।

वैश्विक संकेतों पर निर्भर बाजार

जानकारों के मुताबिक, जनवरी माह में विदेशी निवेशकों की सतर्कता कोई असामान्य बात नहीं है। बीते एक दशक में अधिकांश वर्षों में इस महीने के दौरान एफपीआई ने बाजार से धन निकाला है। आगे का रुख वैश्विक आर्थिक संकेतों और घरेलू बाजार की मजबूती पर निर्भर करेगा, हालांकि वैल्यूएशन दबाव कम होने से निवेश की संभावनाएं बेहतर होती दिख रही हैं।

बाजार में उतरने को तैयार भारत कोकिंग कोल

नौ जनवरी को आ रहा सरकारी क्षेत्र का पहला IPO

सेल पर होंगे कोल इंडिया 47.47 करोड़ इक्विटी शेयर

नई दिल्ली। वर्ष 2026 का पहला सार्वजनिक निर्गम सरकारी क्षेत्र से आने जा रहा है। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) 9 जनवरी को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लॉन्च करेगी। कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल के रूप में होगा, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड अपने 47.47 करोड़ इक्विटी शेयर बाजार में उतारेगी। आईपीओ के तहत निवेशक 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली की प्रक्रिया 8 जनवरी को पूरी की जाएगी। कंपनी द्वारा 5 जनवरी को प्राइस बैंड, लॉट साइज और इश्यू संरचना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी किए जाने की संभावना है। बीसीसीएल की लिस्टिंग सरकार की कोयला क्षेत्र में विनिवेश नीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है।

2025 में जुटाए गए 1.76 लाख करोड़ रुपए

कार्य क्षेत्र की बात करें तो भारत कोकिंग कोल मुख्य रूप से कोकिंग कोल के उत्पादन में संलग्न है, जिसकी मांग स्टील उद्योग में बड़े पैमाने पर रहती है। वहीं सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया की तकनीकी और योजना से जुड़ी इकाई के रूप में कार्य करती है। यह आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है, जब देश का प्राथमिक बाजार मजबूत स्थिति में है। वर्ष 2025 में कंपनियों ने आईपीओ के जरिए करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी और सकारात्मक निवेश माहौल के चलते आने वाले समय में भी प्राथमिक बाजार में गतिविधियां तेज बनी रह सकती हैं।

शीर्ष सात कंपनियों के मार्केट कैप में भारी इजाफा

शेयर बाजार की तेजी का असर, 1.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार मूल्य में 45,266 करोड़ रुपए का लाभ

नई दिल्ली। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में आई मजबूती का सीधा असर देश की प्रमुख कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर देखने को मिला। शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात कंपनियों की संयुक्त मार्केट कैप में करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा लाभ हासिल किया। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सप्ताह भर में 720.56 अंकों की बढ़त के साथ 0.84 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।

इन दिग्गज कंपनियों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार मूल्य में 45,266 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ, जिससे इसकी कुल मार्केट कैप 21.54 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मूल्यांकन में भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला और इसकी बाजार पूंजी 30,414 करोड़ रुपए बढ़कर 9.22 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह लार्सन एंड टुब्रो की मार्केट कैप में 16,204 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 14,626 करोड़ रुपए और एचडीएफसी बैंक में 13,538 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल ने भी सीमित लेकिन सकारात्मक बढ़त हासिल की। हालांकि तेजी के बीच तीन प्रमुख कंपनियों के बाजार मूल्य में कमी भी देखने को मिली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की मार्केट कैप में करीब 10,746 करोड़ रुपए की गिरावट आई। वहीं, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस के बाजार मूल्य में भी क्रमशः 6,183 करोड़ रुपए और 5,694 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। मार्केट कैप के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।

उत्तरी नाइजीरिया में हिंसा का तांडव

गांव पर हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत

एजेंसी । नाइजर

नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में एक बार फिर भीषण हिंसा सामने आई है। नाइजर राज्य के एक गांव में हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि कई ग्रामीणों को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने रविवार को घटना की पुष्टि की है। यह क्षेत्र पहले से ही असुरक्षा और हिंसक घटनाओं की चपेट में है।

गांव में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम नाइजर राज्य के बोरगु लोकल गवर्नमेंट एरिया स्थित कसुवान-दाजी गांव में हथियारबंद लोग अचानक दाखिल हुए। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ग्रामीणों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। हमले के बाद बाजार और कई घरों में आग लगा दी गई, जिससे गांव में भारी तबाही मच गई।

लापता ग्रामीणों से बढ़ी चिंता

नाइजर स्टेट पुलिस के प्रवक्ता वासियू अबियोदुन ने बताया कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या 37 या उससे अधिक हो सकती है, क्योंकि कई ग्रामीण अब भी लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

हिंसा से जूझता उत्तरी नाइजीरिया

अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद नाइजीरिया के कई दूरस्थ इलाकों में सुरक्षा हालात बेहद कमजोर हैं। इन क्षेत्रों में हथियारबंद गिरोह सक्रिय हैं, जो गांवों पर हमले, हत्याएं और फिरौती के लिए अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस के अनुसार, कसुवान-दाजी पर हमला करने वाले हमलावर नेशनल पार्क फॉरेस्ट और काबे जिले की ओर से आए थे। घने और सुनसान जंगल इन गिरोहों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन जाते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हमले के काफी समय बाद तक भी सुरक्षा बल गांव नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि पुलिस और सेना की मौजूदगी नहीं दिखी, जिससे लोगों में डर और नाराजगी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अगवा किए गए ग्रामीणों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात कर दिया गया है।

मनरेगा पर कांग्रेस का हमला

नई कमेटी गठित, 10 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ संग्राम'

मुंबई। मनरेगा कानून का नाम बदलकर VB-G RAM G किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने इसे मनरेगा की मूल भावना पर हमला बताते हुए 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 जनवरी से देशभर में शुरू होगा। आंदोलन की निगरानी के लिए कांग्रेस ने अजय माकन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति (कोऑर्डिनेशन कमेटी) का गठन किया है।

पंचायत से संसद तक आंदोलन

कांग्रेस ने साफ किया है कि 'मनरेगा बचाओ संग्राम' केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा। पार्टी कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर संसद तक इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया जाएगा और ग्रामीण भारत में इसके प्रभाव को लेकर जनजागरण किया जाएगा।

कानून बदलने पर कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस का आरोप है कि नया VB-G RAM G कानून मनरेगा की आत्मा को कमजोर करता है और इससे काम का अधिकार एक कानूनी हक नहीं रह जाएगा। पार्टी ने इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को भी गंभीर मुद्दा बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बदलाव गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

क्या है VB-G RAM G कानून

VB-G RAM G का पूरा नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' है। यह कानून पिछले वर्ष दिसंबर में संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और गांवों में रोजगार के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

गांधी नाम हटाने पर सियासत तेज

इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। संसद में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामा हुआ था। बावजूद इसके कानून लागू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।

न्यूज़ ब्रीफ

पहाड़ की बेटी के अपमान का आरोप, भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ किया पुतला दहन

हरिद्वार। महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं की कथित अपमानजनक टिप्पणियों और पहाड़ की बेटी की दुखद मौत पर राजनीति किए जाने के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चंद्रशेखर चौक पर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। रविवार को बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता चंद्रशेखर चौक पर एकत्र हुईं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया।

रुड़की भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह ने कहा कि पहाड़ की बेटी की मौत जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा राजनीति करना उनकी सोच और मानसिकता को उजागर करता है।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की UAE और श्रीलंका यात्रा, रक्षा सहयोग को बढ़ावा

नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। यह दौरा दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करने के लिहाज से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। UAE में जनरल द्विवेदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा और वे वहां के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा और अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। 7-8 जनवरी को श्रीलंका की यात्रा के दौरान सेना प्रमुख श्रीलंका सेना के कमांडर, रक्षा उप मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे।

वैशाली में पुलिस पर गंभीर आरोप

छापेमारी के दौरान लाखों के गहने गायब

थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित

वैशाली। बिहार के वैशाली जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान बरामदगी में गड़बड़ी के आरोपों के बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लालगंज थानाध्यक्ष और एक दारोगा को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, 31 दिसंबर को लालगंज थाना पुलिस ने हाजीपुर के बिलनपुर गांव निवासी कुख्यात चोर रामप्रीत सहनी के घर छापेमारी की थी। पुलिस ने उस वक्त चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस सहित अन्य सामान बरामद करने की बात कही थी। बाद में आरोप लगे कि छापेमारी के दौरान सोना, चांदी और नकदी भी मिली थी, जिसे जब्ती सूची में शामिल नहीं किया गया। आरोपी के परिजनों का दावा है कि पुलिस टीम घर से लाखों रुपये नकद, करीब 2 किलोग्राम सोना और 6 किलोग्राम चांदी अपने साथ ले गई, लेकिन इन वस्तुओं का कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया।

एसपी की कार्रवाई, जांच तेज

शिकायत सामने आने के बाद वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दारोगा सुमन झा को निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है।

तमिलनाडु चुनाव 2026

डीएमके का सियासी आक्रामक रुख

चार दिनों में सीएम स्टालिन की तीन बड़ी घोषणाएं

एजेंसी । चेन्नई

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महज चार दिनों में तीन अहम घोषणाएं कर राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है।

TAPS लागू करने का ऐलान

3 जनवरी को मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS) लागू करने की घोषणा की। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसके बाद जैक्टो-जियो संगठन ने 6 जनवरी को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन रद्द करने का ऐलान किया।

घोषणापत्र की तैयारी तेज

डीएमके ने सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में चुनावी घोषणापत्र समिति का गठन किया है। जनता से सुझाव जुटाने के लिए पार्टी ने एक विशेष ऐप भी लॉन्च किया है। वहीं एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने भी घोषणापत्र समिति बनाई है, जो 7 से 20 जनवरी तक राज्यभर में दौरा कर विभिन्न वर्गों की मांगें सुनेगी।

चुनावी मोड में तमिलनाडु की सियासत

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो चुके हैं। जहां डीएमके सत्ता बरकरार रखने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है, वहीं एआईएडीएमके सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। इसी बीच अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के गठन से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इससे दोनों प्रमुख दलों पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है।

पोंगल पर 3000 रुपये का तोहफा

4 जनवरी को मुख्यमंत्री ने 22 लाख राशन कार्डधारकों को पोंगल के मौके पर 3000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की। पहले केवल खाद्यान्न और गन्ना देने का ऐलान हुआ था, लेकिन नकद सहायता के फैसले ने सरकार की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। 5 जनवरी को चेन्नई में मुख्यमंत्री 20 लाख कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में सरकारी इंजीनियरिंग, कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, विधि, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के 10 लाख छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए डेल, एसर और एचपी जैसी कंपनियों के उपकरण शामिल किए गए हैं।

इंडिगो प्रकरण की जांच रिपोर्ट DGCA को सौंपी

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में सामने आए तकनीकी व्यवधान को लेकर गठित जांच समिति की रिपोर्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को सौंप दी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि रिपोर्ट में उठाए गए सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर एयरलाइंस से अतिरिक्त जानकारी व स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी नियम यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। खास तौर पर पावर बैंक और लिथियम बैटरी जैसी संवेदनशील वस्तुओं को लेकर DGCA कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करता। इसके लिए तकनीकी अध्ययन, गहन शोध और विशेषज्ञों की राय ली जाती है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियम

राम मोहन नायडू ने बताया कि DGCA के अधिकांश नियम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। इन नियमों को तय करने से पहले अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से व्यापक चर्चा की जाती है। नियम लागू होने के बाद उनका सख्ती से पालन कराना सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होता है।

लिथियम बैटरी को लेकर नई एडवाइजरी

DGCA ने विमान में लिथियम बैटरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर से एक नई एडवाइजरी लागू की है। इसके तहत एयरलाइंस को लिथियम बैटरी के परिवहन से पहले सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करने, यात्रियों को ऑनबोर्ड अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक करने और पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आग लगने की घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केबिन बैगेज में पावर बैंक और स्पेयर बैटरी की कड़ी निगरानी, केबिन क्रू की ट्रेनिंग की समीक्षा और यात्रियों को किसी भी डिवाइस में ओवरहीटिंग या धुआं दिखने पर तुरंत क्रू को सूचना देने की सलाह भी दी गई है।

हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में समिति ने किया आक्रोश प्रदर्शन

धनबाद। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को सनातन धर्म जागरण समिति के आह्वान पर आक्रोश प्रदर्शन सह धरना आयोजित किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। धरना-प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में मई 2024 से सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

शिक्षा नीति में बदलाव करेगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाए जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी तथा गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है।

रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलैहड़ में स्थित अपने पैतृक गांव भवड़ां में लगभग 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क के उदघाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमलैहड़ स्कूल को भी सीबीएसई का दर्जा दिया गया है। यहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। अमलैहड़ सहित प्रदेश के चार चुनिंदा स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकें।

किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस विधि से उगाई गई फसलों की उच्च मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी को सरकार 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। पांच कनाल भूमि पर हल्दी उगाकर किसान तीन लाख रुपये तक आय अर्जित कर सकते हैं।

बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी प्रदान करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी प्रदान कर रही है। चार कनाल भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर युवा हर साल तीन लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग के बजाय अत्याधुनिक यू.वी. टैक्नोलॉजी और ओजोनेशन प्रक्रिया से पानी की प्यूरिफिकेशन की जा रही है।

वैश्विक तनाव बढ़ा: ताइवान को लेकर अमेरिका की चिंता

एजेंसी । काराकस

वेनेजुएला से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर तनाव गहराता नजर आ रहा है। इस घटनाक्रम का असर सीधे अमेरिका-चीन संबंधों पर पड़ता दिख रहा है। कूटनीतिक हलकों में आशंका जताई जा रही है कि चीन अब ताइवान को लेकर कोई बड़ा रणनीतिक या सैन्य कदम उठा सकता है, जिससे एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

ताइवान के पास बढ़ी सैन्य हलचल

ताइवान के नजदीक जापान का छोटा द्वीप योनागुनी अचानक रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हो गया है। यह द्वीप ताइवान से करीब 70 मील दूर है और टोक्यो की तुलना में ताइपे के ज्यादा नजदीक पड़ता है। कभी पर्यटन और गोताखोरी के लिए पहचाना जाने वाला यह इलाका अब एक अग्रिम सैन्य चौकी में तब्दील हो चुका है। यहां अत्याधुनिक रडार सिस्टम और PAC-3 मिसाइलें तैनात की गई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सैन्य गतिविधियों के कारण संचार नेटवर्क पर भी असर पड़ रहा है। योनागुनी, जापान के ओकिनावा प्रांत का हिस्सा है, जहां अमेरिका की मजबूत सैन्य मौजूदगी है। अमेरिका-जापान सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका ने जापान में लगभग 55 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं, जिनमें से 30 हजार से अधिक ओकिनावा में हैं। यह इलाका ताइवान से लगभग 360 मील की दूरी पर है।

अमेरिका-जापान ने तेज की सैन्य तैयारियां

संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका और जापान ने सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। हाल ही में दोनों देशों ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'Resolute Dragon' आयोजित किया, जिसमें करीब 20 हजार सैनिक शामिल हुए। इस अभ्यास में Typhon मिसाइल सिस्टम और Nemesis एंटी-शिप मिसाइल जैसे उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया गया। अमेरिका ने योनागुनी समेत आसपास के द्वीपों पर अस्थायी ईंधन ठिकाने बनाए हैं और तेज सैन्य तैनाती की रणनीति पर काम शुरू किया है। इसके साथ ही फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और गुआम स्थित सैन्य अड्डों को भी सतर्क किया गया है।

चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता से चिंता

बीते कुछ वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा किया है। उसके पास अब सैनिकों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की संख्या अमेरिका से अधिक बताई जा रही है। साथ ही, चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी तेजी आई है। चीन लगातार यह दोहराता रहा है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा।

ताइवान ने बढ़ाया रक्षा बजट

ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया है। उसने रक्षा बजट बढ़ाकर GDP का 3.3 प्रतिशत कर दिया है और 2030 तक इसे 5 प्रतिशत तक ले जाने की योजना बनाई है। अमेरिका की ओर से ताइवान को HIMARS रॉकेट सिस्टम, जैवलिन मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण देने की घोषणा की गई है, हालांकि इनकी आपूर्ति में समय लगने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ने ताइवान को निर्णायक समर्थन नहीं दिया, तो चीन के सामने ताइवान के लिए टिक पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में वेनेजुएला से उपजा तनाव अब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बड़े भू-राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिख रहा है।

खबर चुनावी है

नामांकन वापसी पर विवाद, 3 उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस शिकायत

ठाणे। नगर निगम चुनाव में बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। आर्थिक लालच में आकर चुनाव से नामांकन वापस लेने के आरोप में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट (यूबीटी) के तीन उम्मीदवारों—दादाभाऊ रेपाले, स्नेहा नांगरे और विक्रांत घाग—के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत यूबीटी के नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे तथा मनसे नेता अविनाश जाधव ने श्रीनगर पुलिस थाने में दी है, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन उम्मीदवारों ने आर्थिक प्रलोभन और सरकारी तंत्र के दबाव में आकर चुनाव से नाम वापस लिया, जिससे मतदाताओं के साथ धोखा हुआ और उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। एमवीए नेताओं का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा है और नागरिकों में भारी असंतोष फैल गया है। बताया गया कि ठाणे महापालिका चुनाव में यूबीटी गुट ने इन तीनों को एबी फॉर्म देकर आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन स्थानीय पार्टी नेतृत्व को बिना बताए इन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। इसके चलते शिंदे गुट के तीन उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए।

मनसे उम्मीदवारों को नामांकन वापसी के लिए 5 करोड़ की पेशकश का आरोप

ठाणे। नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अविनाश जाधव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पक्षों ने मनसे उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए 5 करोड़ रुपये की पेशकश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन, धनबल और चुनाव अधिकारियों के दुरुपयोग के जरिए छह नगरसेवकों को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया। महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव निर्णय अधिकारी वृषाली पाटील और सत्वशीला शिंदे के फोन कॉल, सीसीटीवी फुटेज और बैंक खातों की जांच की मांग की है। साथ ही दोनों अधिकारियों को तुरंत हटाकर नए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई है। एमवीए ने चेतावनी दी है कि यदि अगले दिन तक निर्णय नहीं लिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अविनाश जाधव और शिवसेना (उद्धव गुट) के पूर्व सांसद राजन विचारे ने दावा किया कि नामांकन वापसी के दिन एक पुलिस अधिकारी उद्धव गुट के उम्मीदवार विक्रांत घाग को उपमुख्यमंत्री शिंदे के बंगले पर ले गया।

क्या बोलती पब्लिक

बीएमसी चुनाव में मतदाता विकास और भरोसेमंद नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ नया आज़माना चाहते हैं, तो कई पारंपरिक दलों पर विश्वास जता रहे हैं।

–अनीषा सिन्हा, मीरा रोड

बीएमसी चुनाव को लेकर मतदाता स्थानीय मुद्दों और कामकाज के रिकॉर्ड को महत्व दे रहे हैं। बदलाव की चाह भी है, लेकिन भरोसे की राजनीति अब भी असरदार है।

–पूजा पुरोहित, ऐरोली

हमें भेजें

अगर आप भी अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो 8356804318 इस नंबर पर व्हाट्सप्प करें।

महानगरपालिका चुनाव 2026

मुंबई की सत्ता का संग्राम

आंकड़ों से लेकर ज़मीन तक

धीरज सिंह। मुंबई

करीब नौ साल के लंबे अंतराल के बाद मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 आखिरकार शहर की राजनीति के केंद्र में आ गया है। 15 जनवरी 2026 को होने वाले इस चुनाव में 227 वार्डों में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। देश के सबसे अमीर नगर निगम की सत्ता के लिए यह मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि आंकड़ों, सामाजिक समीकरणों और ज़मीनी मुद्दों की भी सीधी टक्कर है। इस बार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल असामान्य रूप से गर्म है। वजह साफ है- एक ओर बदले हुए गठबंधन, दूसरी ओर बदली हुई मतदाता संरचना और तीसरी ओर मुंबई की रोज़मर्रा की समस्याएं, जो अब सीधे वोट से जुड़ गई हैं।

मतदाता बढ़े, प्राथमिकताएं बदलीं

चुनाव आयोग की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, इस बार BMC चुनाव में कुल 1,03,44,315 मतदाता पंजीकृत हैं। यह संख्या 2017 के चुनाव की तुलना में करीब 12 लाख अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 48 .26 लाख तक पहुंच गई है, जो अब निर्णायक स्थिति में मानी जा रही है। ज़मीन पर इसका असर साफ दिखता है। अंधेरी, गोरेगांव, कुर्ला और घाटकोपर जैसे इलाकों में प्रचार के दौरान पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और सुरक्षा जैसे मुद्दे अब पोस्टर से ज़्यादा बातचीत का हिस्सा हैं। राजनीतिक दल भी अब “बड़े नैरेटिव” के साथ-साथ वार्ड स्तर के मुद्दों पर फोकस करते दिख रहे हैं।

वार्डों का असंतुलन और चुनावी दबाव

BMC के 227 वार्डों में मतदाता संख्या समान नहीं है। कुर्ला, अंधेरी पश्चिम और घाटकोपर जैसे वार्डों में 60 हजार से अधिक मतदाता हैं, जबकि कुछ वार्डों में यह संख्या 30 हजार के आसपास सिमटी हुई है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, ज्यादा मतदाता वाले वार्डों में जीत अब सिर्फ प्रचार से नहीं, बल्कि बूथ-लेवल मैनेजमेंट से तय हो रही है। वहीं छोटे वार्डों में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय काम सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है।

स्विंग वार्ड: जहां चुनाव पलटेगा

चुनाव की असली लड़ाई करीब 60 से 70 ऐसे वार्डों में मानी जा रही है, जहां मुकाबला बेहद करीबी है। कुर्ला, गोवंडी, चेंबूर पूर्व, जोगेश्वरी पूर्व, अंधेरी पूर्व और विक्रोली पश्चिम जैसे इलाकों में हर वोट की कीमत बढ़ गई है। इन वार्डों में MNS, निर्दलीय और स्थानीय प्रभावशाली उम्मीदवार परिणाम तय कर सकते हैं। कई जगह पिछले चुनावों में जीत-हार का अंतर 3 से 5 प्रतिशत के भीतर रहा है, और इस बार भी स्थिति वैसी ही दिख रही है।

महिलाएं और स्थानीय चेहरे निर्णायक

इस बार दलों ने महिला उम्मीदवारों को पहले से ज्यादा टिकट दिए हैं। ज़मीनी रिपोर्ट बताती है कि महिला मतदाता अब केवल समर्थक नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाली वोटर बन चुकी हैं-खासकर पानी, स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। स्थानीय चेहरे, जो वार्ड में नियमित दिखते हैं, इस चुनाव में पार्टी से भी ऊपर रखे जा रहे हैं। कई जगह पार्टी बदलने के बावजूद उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ कायम दिख रही है।

महायुति : उपनगरों में संगठित बढ़त

भाजपा और शिंदे गुट शिवसेना की महायुति इस चुनाव में उपनगरों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी पश्चिम, भांडुप और मुलुंड जैसे इलाकों में महायुति का संगठन ज़मीनी स्तर पर सक्रिय दिखता है। इन इलाकों में मेट्रो, सड़कें, फ्लाईओवर, ड्रेनेज और पुनर्विकास जैसे मुद्दों पर मतदाताओं से संवाद किया जा रहा है।घाटकोपर और मुलुंड जैसे पूर्वी उपनगरों में मध्यम वर्ग और व्यापारिक समुदाय महायुति की ओर झुका हुआ नजर आता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार, “यहां वोट अब भावनात्मक से ज्यादा परफॉर्मेंस-बेस्ड हो गया है।”

आइलैंड सिटी में परंपरा और पकड़

दक्षिण और मध्य मुंबई में तस्वीर अलग है। दादर, माहिम, वर्ली, परेल, भायखला और प्रभादेवी जैसे इलाकों में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना और कांग्रेस का पारंपरिक आधार अब भी कायम है। यहां मराठी अस्मिता, पुराना संगठन, स्थानीय शाखाएं और नेताओं की व्यक्तिगत पहुंच आज भी असर दिखाती है। कई इलाकों में लोग मानते हैं कि “नगरसेवक वही अच्छा, जो मोहल्ले में दिखे।” मध्य मुंबई के कुर्ला पश्चिम, सायन और चेंबूर पश्चिम में भी MVA को अल्पसंख्यक और मराठी वोटों के मेल से ताकत मिलती दिख रही है।

चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, शहर का भविष्य

BMC चुनाव 2026 केवल पार्षद चुनने का मामला नहीं है। यह चुनाव मुंबई के बजट, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, पुनर्विकास और शहरी जीवन की दिशा तय करेगा। एक ओर उपनगरों में महायुति बढ़त लेने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर आइलैंड सिटी में MVA अपनी जमीन बचाने में जुटी है। फैसला उन मतदाताओं के हाथ में है, जो अब नारे नहीं, काम का हिसाब मांग रहे हैं। 15 जनवरी को होने वाला मतदान और 16 जनवरी की मतगणना यह तय करेगी कि मुंबई की सबसे ताकतवर संस्था की बागडोर किसके हाथ जाएगी-और आने वाले पांच सालों तक शहर किस रास्ते पर चलेगा।

शालेय विद्यार्थियों ने संकल्प पत्र के जरिए अभिभावकों से किया मतदान का आग्रह

‘हमारा संकल्प-100 प्रतिशत मतदान’ अभियान के तहत अनूठी पहल

दोपहर संवाददाता। नवी मुंबई

15 जनवरी 2026 को होने वाले नवी मुंबई महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव में अधिकतम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए नवी मुंबई महानगरपालिका की ओर से निर्वाचन विषयक स्वीप (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। महानगरपालिका आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में यह पहल संचालित की जा रही है।

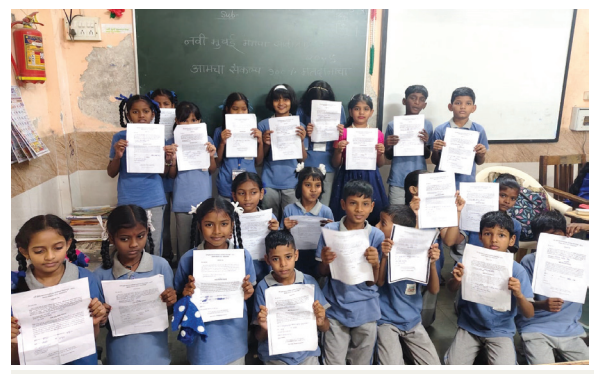

अभिभावकों का लिखित संकल्प

संकल्प पत्र के दूसरे भाग में ‘माता-पिता का संकल्प’ शामिल है, जिसमें अभिभावक यह शपथ लेते हैं कि वे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान के अमूल्य अधिकार का हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। साथ ही परिवार के सदस्यों और परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। संकल्प में यह भी उल्लेख है कि वे किसी भय, प्रलोभन या दबाव में आए बिना, धर्मनिरपेक्ष भावना के साथ मतदान करेंगे। इस भाग में अभिभावक अपने हस्ताक्षर और नाम दर्ज करते हैं।

स्कूलों में ‘मतदान संकल्प पत्र’ अभियान

इसी कड़ी में ‘हमारा संकल्प—100 प्रतिशत मतदान’ शीर्षक के तहत नवी मुंबई के स्कूलों में मतदान संकल्प पत्र नामक अभिनव उपक्रम शुरू किया गया है। नवी मुंबई महानगरपालिका स्कूल क्रमांक 52, दिघा में विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पूरे उत्साह के साथ इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आने वाले दिनों में महानगरपालिका और निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों में यह उपक्रम लागू किया जा रहा है।

'प्रिय माँ-पापा' से शुरू होता है संदेश

दो भागों में तैयार इस संकल्प पत्र का पहला हिस्सा ‘प्रिय माँ-पापा’ संबोधन से शुरू होता है। इसमें विद्यार्थी अपने अभिभावकों से आग्रह करते हैं कि वे उनके उज्ज्वल भविष्य और देश की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 15 जनवरी 2026, गुरुवार को नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प लें। इस हिस्से में विद्यार्थी अपना पूरा नाम, कक्षा और स्कूल का नाम दर्ज करते हैं।

ठाणे वार्ड 17

नेतृत्व और विकास का चेहरा

ठाणे। वार्ड 17-जिसमें किसन नगर 2, नेहरू नगर और अंबिका नगर, भटवाडी, शिव टेकडी, धाम लाइन, शामिल हैं। ठाणे के उन इलाकों में से एक है जहां नागरिक सेवा, स्थानीय नेतृत्व और बड़े राजनीतिक गठबंधनों की ताक़त सीधे वोटों में बदलती है। यह वार्ड इस बार शिवसेना के नगरसेवक योगेश तातोबा जानकर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रभाव क्षेत्र में आता है और अब महायुति के साथ बीजेपी का भी समर्थन जोड़ लिया गया है।

चुनावी पृष्ठभूमि और लोकप्रियता

2017 में योगेश जानकर ने वार्ड 17 से लगभग 15,269 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की थी। उनके मुकाबले भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन जानकर को स्थानीय जनता में अपार लोकप्रियता हासिल है। एक बहुत बड़ी भीड़ योगेश जानकर की पीछे घूम रही है। इस बार बीजेपी के समर्थन से जानकर को संगठनात्मक मजबूती और संसाधनों का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उनके लिए जीत की राह और मजबूत हो सकती है। स्थानीय मतदाता उन्हें जमीनी काम और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जानते और पसंद करते हैं।

जानकर की पकड़ मजबूत

वार्ड 17 में योगेश जानकर की पकड़ मजबूत है, लेकिन यह इलाका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण राजनीतिक दबाव भी अधिक है। बीजेपी का साथ और महायुति गठबंधन जानकर को अतिरिक्त संगठनात्मक और संसाधनात्मक शक्ति देता है, लेकिन मतदाता अपेक्षाएं और स्थानीय शिकायतें अभी भी निर्णायक कारक हैं। वार्ड 17 में योगेश जानकर की लोकप्रियता और बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें चुनाव में मजबूत स्थिति देती है। वहीं, विकास की तेज़ अपेक्षाएँ और स्थानीय नागरिकों की निरंतर निगरानी उन्हें लगातार सक्रिय और जवाबदेह

जमीनी मुद्दे

वार्ड के निवासियों की रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं-पानी की अनियमित आपूर्ति, सड़क और कचरा प्रबंधन, बिजली और ट्रैफिक जाम। किसन नगर और नेहरू नगर में गर्मियों में पानी की कमी मुख्य चिंता है। अंबिका नगर और MIDC क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के कारण ट्रैफिक और सुरक्षा पर स्थानीय मतदाता सतर्क हैं।

शिवसेना बनाम शिवसेना

अस्तित्व की लड़ाई है यह चुनाव

दोपहर संवाददाता। नवी मुंबई

मुंबई की राजनीति इस बार बेहद कांटे की लड़ाई में बदल गई है। 2026 के BMC चुनाव में किसी भी गली, किसी भी वार्ड का रूझान साफ नहीं है, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यह अभी तय नहीं। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा शिवसेना के दो गुटों के बीच है। दोनों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट है, जिसे पिछले BMC चुनाव में लगभग 84 सीटें मिली थीं। 2017 के चुनाव में शिवसेना ने कुल 227 सीटों में से 84 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने 82 और कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन ने 76 सीटें हासिल की थीं। इसके बाद मुंबई में शिवसेना का जनाधार काफी मजबूत माना जाता रहा, खासकर पुराने शहर और पूर्वी उपनगरों में।

शिंदे गुट की पहली बड़ी परीक्षा

दूसरी तरफ शिंदे गुट है, जो उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद पहली बार BMC चुनाव में उतर रहा है। शिंदे गुट के पास अब लगभग 40 से 50 के करीब शिवसेना के नगरसेवक और दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें भाजपा के सहयोग से चुनाव लड़ने में मदद कर रहे हैं। यह उनके लिए पहला बड़ा अखाड़ा है, और परिणाम तय करेंगे कि उनका जनाधार कितना मजबूत है। विशेष रूप से यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना के पूर्व नगरसेवक और स्थानीय कार्यकर्ता कितने शिंदे गुट के साथ आए हैं।

मुंबई में लगभग 50% मतदाता युवा हैं

चुनाव के दौरान कई रिपोर्टों और सर्वेक्षणों ने बताया कि मुंबई में लगभग 50% मतदाता युवा हैं, जो पिछले अनुभव या पारंपरिक पार्टी आधार से प्रभावित नहीं हैं। यही कारण है कि यह चुनाव अत्यधिक अनिश्चित और रोमांचक माना जा रहा है। संक्षेप में, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कौन जीत रहा है। मुंबई की सत्ता की इस लड़ाई में शिंदे गुट की पहली परीक्षा और उद्धव गुट की ताकत दोनों एक साथ देखी जाएगी। परिणाम ही बताएंगे कि राजनीतिक पेंडुलम किस दिशा में झूलता है।